

वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट सारांश

2021/2

शिक्षा में गैर-सरकारी कार्यकर्ता

कौन चुनता है? कौन वंचित रह जाता है?

unesco

सतत विकास लक्ष्य

Global Education Monitoring Report

वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट सारांश

2021/2

शिक्षा में गैर-सरकारी कार्यकर्ता

कौन चुनता है? कौन वंचित रह जाता है?

शिक्षा 2030 इंचियोन घोषणा और ढांचा कार्रवाई में यह निर्दिष्ट किया गया है कि *वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट* का अधिदेश "एसडीजी 4 और अन्य एसडीजी में शिक्षा पर निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए तंत्र" बनाना है जिसे "राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यनीतियों को लागू करने की सूचना देने का दायित्व सौंपा गया है ताकि समग्र एसडीजी अनुवर्ती कार्रवाई और समीक्षा के भाग के रूप में सभी संबंधित भागीदारों को उनकी प्रतिबद्धताओं के लिए जिम्मेदार ठहराने में मदद की जा सके। इसे यूनेस्को द्वारा आयोजित एक स्वतंत्र टीम द्वारा तैयार किया गया है।

इस प्रकाशन में दिए गए पदनाम और प्रस्तुत सामग्री का अर्थ किसी देश, प्रदेश, सीमा, नगर या क्षेत्र या इसके प्राधिकारियों या इसकी सीमाओं का सीमांकन करने के संबंध में यूनेस्को की ओर से कोई राय, जो कोई भी हो, अभिव्यक्त करना नहीं है।

वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट टीम इस रिपोर्ट में शामिल तथ्यों के चयन और प्रस्तुति तथा इसमें व्यक्त राय के लिए जिम्मेदार है, जो जरूरी नहीं यूनेस्को के हों, और संगठन इसके लिए प्रतिबद्ध नहीं है। रिपोर्ट में व्यक्त विचारों और राय की पूरी जिम्मेदारी इसके निदेशक की है।

वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट टीम

निदेशक: मैनोस एंटोनिनिस

डैनियल एप्रिल, बिलाल बरकत, मार्सेल मारिया बारियोस रिवेरा, मेडेलीन बैरी, कैथरीन ब्लैक, निकोल बेला, सेलिया यूजेनिया काल्वो गुटिरेज़, डैनियल कारो वास्केज़, अन्ना क्रिस्टीना डी'एडियो, दिमित्रा डफलिया, दमिली डेविडोव, फ्रांसिस्का एंड्रीज़ी, कॉन्स्टैंज़ा जिनेस्ट्रा, चांदनी जैन,

प्रियदर्शनी जोशी, मारिया-राफ़ेला कलदी, जोसफिन कियान्जे, क्रेग लेयर्ड, केटी लाज़ारो, कैट लिंकिन्स, कैमिला लीमा डे मोरेस, कसियानि लिथ्रोंगोमाइटिस, अनीसा मेक्टर, क्लॉडिन मुकिज़वा, युकी मुराकामी, मैनुएला पोम्बो पोलांको, जूडिथ रंड्रियाटोविना, कैट रेडमैन, मारिया रोजनोव, लौरा स्टिपानोविक, उलरिच जानसे वैन वूरेन, जुलियाना ज़ापाटा, लमा ज़ेक्रया तथा जियाहेंगो झोउ

वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट एक स्वतंत्र वार्षिक प्रकाशन है। जीईएम रिपोर्ट सरकारों, बहुपक्षीय एजेंसियों और निजी फाउंडेशनों के एक समूह द्वारा वित्त-पोषित है और यूनेस्को द्वारा समर्थित है।

वर्तमान लाइसेंस विशेष रूप से पाठ्य सामग्री पर लागू होता है। छवियों का उपयोग करने के लिए पूर्व अनुमति ली जाएगी।

यूनेस्को एक स्वतंत्र सर्व सुलभ प्रकाशक है और सभी प्रकाशन यूनेस्को के दस्तावेज संग्रह के माध्यम से नि:शुल्क ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाते हैं। यूनेस्को द्वारा इसके प्रकाशनों का कोई व्यावसायीकरण कागज या सीडी पर सामग्री को प्रिंट करने या नकल करने और वितरण के लिए मामूली वास्तविक लागत की लागत-वसूली के लिए है। इसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं है।

इस प्रकाशन को इस प्रकार संदर्भित किया जा सकता है: यूनेस्को 2021. *वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट सारांश 2021/2: शिक्षा में गैर-सरकारी कार्यकर्ता: कौन चुनता है? कौन वंचित रह जाता है? पेरिस, यूनेस्को।*

© यूनेस्को, 2021
पहला प्रकाशन
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक
संगठन द्वारा 2021 में प्रकाशित
7, प्लेस डी फोंटेनॉय, 75352 पेरिस 07 एसपी, फ्रांस

यूनेस्को द्वारा टाइपसेट
ग्राफिक डिजाइन ऑप्टिमा ग्राफिक डिजाइन कंसल्टेंट्स लिमिटेड द्वारा
लेआउट ऑप्टिमा ग्राफिक डिजाइन कंसल्टेंट्स लिमिटेड द्वारा

आवरण चित्र: जाप जोरिस वेन्स/
सुपर फॉर्मोसा फोटोग्राफी
शीर्षक: स्कूल के विभिन्न मार्ग, नीदरलैंड

चित्र हाउसटोनिक एसआरएल यूनिपर्सोनाले द्वारा
कार्टून जूलियो कैरिओन क्यूवा (कैरी)
और मिगुएल मोरालेस मेड्रिगल द्वारा

इनफोग्राफिक्स हाउसटोनिक एसआरएल यूनिपर्सोनाले द्वारा

ईडी-2021/डब्ल्यूएस/38

यह प्रकाशन ऐट्रिब्यूशन-शेयरएलाइक 3.0 आईजीओ (सीसी-बीवाई-एसए 3.0 आईजीओ) लाइसेंस (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/) के अंतर्गत सभी के लिए उपलब्ध है। इस प्रकाशन की सामग्री का प्रयोग करने पर इसका उपयोगकर्ता यूनेस्को के सर्व सुलभ संग्रह (http://www.unesco.org/open-access/ terms-use-ccbysa-en). के इस्तेमाल की शर्तों को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा)।

वर्तमान लाइसेंस विशेष रूप से प्रकाशन की पाठ्य सामग्री पर लागू होता है। किसी भी सामग्री के प्रयोग के लिए, जो स्पष्ट रूप से यूनेस्को से संबंधित न हो, के लिए निम्नलिखित से पूर्व अनुमति का अनुरोध किया जाएगाः publication.copyright@unesco.org या यूनेस्को पब्लिशिंग, 7, प्लेस डी फोन्टेनोए, 75352 पेरिस 07 एसपी फ्रांस।

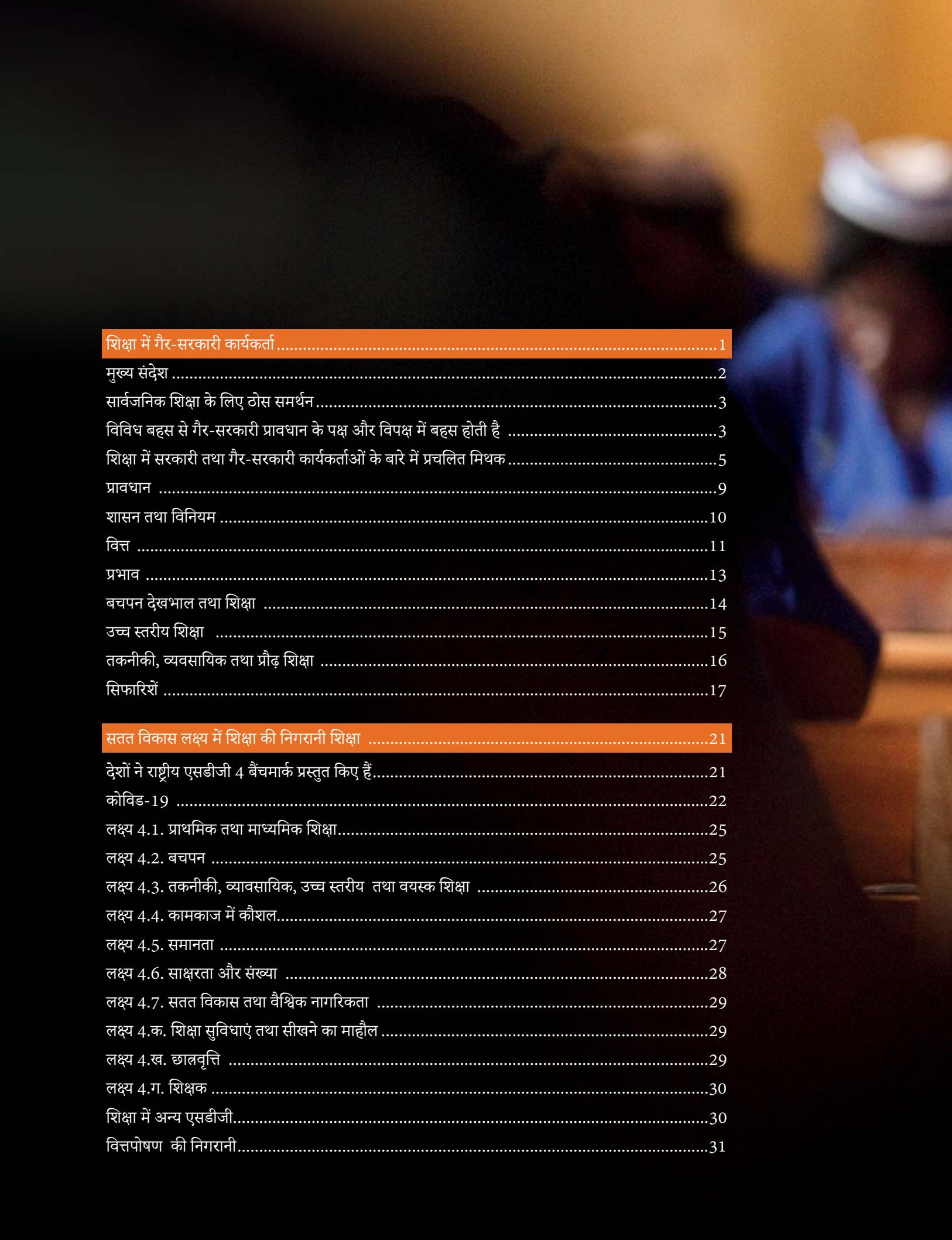
वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट श्रृंखला

2021/2022	शिक्षा में गैर-सरकारी कार्यकर्ता: कौन चुनता है? कौन वंचित रह जाता है?
2020	समावेश और शिक्षा: सब यानी सभी
2019	पलायन, विस्थापन और शिक्षा: संपर्क बनाएं, बाधाएं नहीं
2017/8	शिक्षा में जवाबदेही: अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हुए
2016	लोगों और संपूर्ण पृथ्वी के लिए शिक्षा: सभी के लिए सुनिश्चित भविष्य का सृजन

ईएफए वैश्विक निगरानी रिपोर्ट श्रृंखला

2015	सभी के लिए 2000-2015 तक शिक्षा: उपलब्धियां और चुनौतियाँ
2013/4	अध्यापन और शिक्षण: सभी के लिए गुणवत्ता प्राप्त करना
2012	युवा और कौशल: शिक्षा को कार्य से जोड़ना
2011	छिपा संकट: सशस्त्र संघर्ष और शिक्षा
2010	उपेक्षित वर्गों तक पहुंच बनाना
2009	असमानता दूर करना: शासन क्यों जरूरी है
2008	2015 तक सभी के लिए शिक्षा: क्या हम इसे पूरा करेंगे?
2007	ठोस आधार: शुरुआती बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा
2006	जीवन के लिए साक्षरता
2005	सभी के लिए शिक्षा: गुणवत्ता की अनिवार्यता
2003/4	जेंडर और सभी के लिए शिक्षा: समानता की ओर कदम
2002	सभी के लिए शिक्षा: क्या दुनिया सही रास्ते पर है?

इस रिपोर्ट का सारांश और सभी संबंधित सामग्री http://bit.ly/2021gemreport से डाउनलोड की जा सकती है:



शिक्षा में गैर-सरकारी कार्यकर्ता 1

मुख्य संदेश 2

सार्वजनिक शिक्षा के लिए ठोस समर्थन 3

विविध बहस से गैर-सरकारी प्रावधान के पक्ष और विपक्ष में बहस होती है 3

शिक्षा में सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं के बारे में प्रचलित मिथक 5

प्रावधान 9

शासन तथा विनियम 10

वित्त 11

प्रभाव 13

बचपन देखभाल तथा शिक्षा 14

उच्च स्तरीय शिक्षा 15

तकनीकी, व्यवसायिक तथा प्रौढ़ शिक्षा 16

सिफारिशें 17

सतत विकास लक्ष्य में शिक्षा की निगरानी शिक्षा 21

देशों ने राष्ट्रीय एसडीजी 4 बैंचमार्क प्रस्तुत किए हैं 21

कोविड-19 22

लक्ष्य 4.1. प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा 25

लक्ष्य 4.2. बचपन 25

लक्ष्य 4.3. तकनीकी, व्यावसायिक, उच्च स्तरीय तथा वयस्क शिक्षा 26

लक्ष्य 4.4. कामकाज में कौशल 27

लक्ष्य 4.5. समानता 27

लक्ष्य 4.6. साक्षरता और संख्या 28

लक्ष्य 4.7. सतत विकास तथा वैश्विक नागरिकता 29

लक्ष्य 4.क. शिक्षा सुविधाएं तथा सीखने का माहौल 29

लक्ष्य 4.ख. छात्रवृत्ति 29

लक्ष्य 4.ग. शिक्षक 30

शिक्षा में अन्य एसडीजी 30

वित्तपोषण की निगरानी 31



साभार: यूनिसेफ/ ओलिविए अस्सेली

शिक्षा में गैर-सरकारी कार्यकर्ता

मुख्य संदेश

शिक्षा का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें गैर-सरकारी कार्यकर्ता शामिल न हों।

साधारण शब्दों में कहें तो, गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं के बिना, 35 करोड़ से अधिक बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर आ जाएगी। लेकिन गैर-सरकारी कार्य बच्चों द्वारा उपयोग की जाने वाली पाठ्यपुस्तकों, कैंटीन में उनका भोजन, उन्हें मिलने वाली अतिरिक्त सहायता, उनके द्वारा सीखे गए कौशल आदि, बहुत कुछ को प्रभावित करते हैं।

अधिकांश लोग सरकारी शिक्षा के पक्ष में हैं।

34 मध्यम और उच्च आय वाले देशों में चार में से तीन लोग शिक्षा पर अधिक सार्वजनिक खर्च को तरजीह देते हैं, जिसमें और अधिक खर्च करने से देश में उतनी ही अधिक असमानता बढ़ेगी। दस में से लगभग नौ लोग सोचते हैं कि शिक्षा प्राथमिक रूप से सार्वजनिक होनी चाहिए।

लेकिन कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों में इस तरह का समर्थन धीरे-धीरे खत्म हो गया है।

जहां सरकारी स्कूलों में आपूर्ति कम हो गई और उनकी गुणवत्ता खराब हो गई थी, कई परिवारों ने अपने बच्चों को इन स्कूलों से निकाल लिया। दुनिया भर में निजी संस्थानों की हिस्सेदारी लगभग 10 वर्षों में 7 प्रतिशत अंक तक बढ़ गई: प्राथमिक में 2013 तक 17% और माध्यमिक शिक्षा में 2014 तक 26% हो गई। यह तब से लगभग स्थिर बनी हुई है। मध्य और दक्षिणी एशिया में निजी दाखिले की हिस्सेदारी प्राथमिक में 36% और माध्यमिक शिक्षा में 48% है।

सार्वजनिक शिक्षा मुफ्त नहीं है।

विश्व स्तर पर परिवार शिक्षा पर कुल 30% खर्च करते हैं जबकि निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों में 39% खर्च करते हैं। यह हिस्सा धनी परिवारों के कारण है जो अपने बच्चों को प्रतिस्पर्धी लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्री-प्राइमरी, प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा पर इसका काफी बड़ा हिस्सा खर्च किया जाता है, जो सरकारें मुफ्त प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लगभग 8% परिवार शिक्षा का खर्च उठाने के लिए उधार लेते हैं, जो निम्न आय वाले देशों में बढ़कर 12% और हैती, केन्या, फिलीपींस और युगांडा में 30% या उससे अधिक हो गया है।

सार्वजनिक शिक्षा प्राय: सभी शामिल नहीं होते।

कई सार्वजनिक शिक्षा प्रणालियाँ जाति और वर्ग के आधार पर पृथक्कता को रोकने में विफल रहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन डेटा कार्यक्रम पर आधारित स्कूलों में सामाजिक विविधता की एक सूची में पाया गया कि 2018 में अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और मैक्सिको में एक ही तरह के उच्च वर्ग का स्तर था, हालांकि केवल चिली की शिक्षा प्रणाली में निजी संस्थानों की उच्च हिस्सेदारी के लिए आलोचना की जाती है।

कोई भी एक प्रकार का प्रदाता किसी अन्य की तुलना में बेहतर शिक्षा प्रदान नहीं करता है।

30 निम्न और मध्यम आय वाले देशों के डेटा से पता चलता है कि, यदि पारिवार को सामान्य विशेषताओं की कसौटी पर कसा जाए, तो निजी स्कूलों में दाखिला लेने की पसंद घटकर आधा यानी दो-तिहाई रह जाती है। 49 देशों में किए गए अध्ययन के एक नमूने से पता चला कि गरीब लोगों की तुलना में सबसे अमीर लोगों के निजी स्कूलों में जाने की संभावना लगभग दस गुना अधिक है। और जो माता-पिता स्कूल चुन सकते हैं, वे ऐसा गुणवत्ता के बजाय धार्मिक आस्था, सुविधाओं और छात्रों की विशेषताओं के कारण करते हैं, जिसके बारे में उन्हें शायद ही कभी पर्याप्त जानकारी होती है।

जहां आवश्यकता अधिक होती है वहां विनियम, निगरानी और कानून लागू करने की क्षमता कम हो जाती है।

पीयर वेबसाइट के लिए 211 शिक्षा प्रणालियों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि विनियम पंजीकरण, अनुमोदन या लाइसेंसिंग (98%), शिक्षक प्रमाणन (93%), बुनियादी ढांचे (80%) और छात्र/ शिक्षक अनुपात (74%) पर ध्यान केंद्रित करते हैं। विनियमों में गुणवत्ता या समानता पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना बहुत कम रहती है: 67% शुल्क निर्धारण को नियंत्रित करते हैं, 55% गैर-सरकारी स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया में छात्रों को चुनिंदा आधार पर चुनने को रोकते हैं, 27% लाभ कमाने पर प्रतिबंध लगाते हैं और केवल 7% के पास वंचित समूहों की पहुंच का समर्थन करने वाले कोटा हैं। निजी शिक्षण 48% देशों में अनियंत्रित है और केवल 11% देशों में वाणिज्यिक कानून नियंत्रित है।

गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं की भूमिका प्रारंभिक बाल शिक्षा, तकनीकी, उच्च स्तरीय और प्रौढ़ शिक्षा में और भी अधिक कारगर ढंग से मौजूद हैं।

यह कभी-कभी यह समानता और गुणवत्ता की कीमत पर होता है। गैर-सरकारी प्रारंभिक बाल शिक्षा और उच्च स्तरीय शिक्षा की आम तौर पर उच्च लागत का अर्थ है कि इन संस्थानों में शहरी अमीर वर्ग का प्रतिनिधित्व अधिक है। अमेरिका में, अधिकतम लाभ कमाने वाले विश्वविद्यालयों को छात्रों के परिणामों में गिरावट के साथ जोड़ा गया है। बाजार प्रतिस्पर्धा या कौशल विकास प्रणालियों के माध्यम से निजी प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों, जैसे ऑस्ट्रेलिया के टीवीईटी फी-हेल्प ऋण कार्यक्रम और भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को निजी प्रावधान की गुणवत्ता बढ़ाने और रोजगार के परिणामों में सुधार करने के लिए जवाबदेही और निगरानी प्रक्रियाओं पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा था।

सरकारों को सभी शिक्षण संस्थानों, छात्रों और शिक्षकों को एक ही प्रणाली के भाग के रूप में देखना चाहिए।

मानकों, सूचनाओं, प्रोत्साहनों और जवाबदेही से सरकारों को विशेषाधिकार या शोषण को नज़रअंदाज किए बिना सभी के शिक्षा के अधिकार की रक्षा, सम्मान और पूरा करने में मदद करनी चाहिए। सरकारी रूप से वित्त-पोषित शिक्षा को सार्वजनिक रूप से प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शिक्षा प्रक्रियाओं, छात्र परिणाम और शिक्षक की कामकाजी परिस्थितियों में असमानता का दृढ़ता से समाधान किया जाना चाहिए। दक्षता और नवाचार कोई व्यावसायिक रहस्य नहीं होना चाहिए; बल्कि उनका विस्तार किया जाना चाहिए और सभी के द्वारा अपनाया जाना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए, सार्वजनिक शिक्षा नीति प्रक्रिया में पारदर्शिता और अखंडता बनाए रखने की आवश्यकता है।

सरकारों ने हमेशा शिक्षा का नेतृत्व नहीं किया है। ऐतिहासिक रूप से, शिक्षा की व्यवस्था धर्म, परिवार और समाज द्वारा अनायास और अनौपचारिक रूप से की जाती थी। अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, राज्यों ने एक शिक्षित कार्यबल के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने और सरकारी स्कूलों के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान की भावना विकसित और सुदृढ़ करने का अवसर देखा। समाज और अर्थव्यवस्था के व्यापक लाभ को देखते हुए सरकारें इस सार्वजनिक वस्तु के वितरण की ऊँची लागत उठाने के लिए तैयार थीं। 20वीं सदी में नए स्वतंत्र देशों के लिए, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली का निर्माण उपनिवेशवाद से मुक्ति की पहचान थी। सार्वजनिक शिक्षा का उद्देश्य हमेशा नेक आदर्शों या सत्तारूढ़ विचारधाराओं को बढ़ावा देना होता है। नई व्यवस्था ने पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था का स्थान लेते हुए उसे अपने में समाहित कर लिया।

फिर भी शिक्षा एक निजी वस्तु है। अधिक शिक्षा प्राप्त करने से व्यक्तिगत अवसरों में सुधार होता है और दूसरों को ऐसे अवसरों से वंचित रखा जा सकता है। जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करते जाते हैं, वे उच्च जीवन स्तर और अधिक लाभ प्राप्त करने की बेहतर स्थिति में होते हैं। चूंकि शिक्षा प्रणाली हर किसी को उच्च स्तर पर समायोजित नहीं कर सकती है, इसलिए परिवार यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करते हैं कि उनकी संतान ही शीर्ष पर पहुंचें। इस तरह की होड़ से मांग पैदा होती है, जिससे शिक्षा प्रदान करने के साधनों और सेवाओं की आपूर्ति शुरू होती है। राष्ट्रीय संदर्भ और मनोवृत्ति के आधार पर, शिक्षा सेवाओं के प्रत्यक्ष प्रावधान में बाजार उभर सकते हैं जो लाभ प्रदान करते हैं।

सार्वजनिक शिक्षा के लिए ठोस समर्थन

शिक्षा के विकल्प बच्चों के जीवन का निर्धारण करते हैं। माता-पिता को केवल खर्च और लाभ-हानि पर ही नहीं, बल्कि इससे जुड़े कई संबंधित पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए। क्या पढ़ाया जाता है, कैसे, किसके द्वारा और कहाँ पढ़ाया जाता है, इसके बारे में विकल्प दुनिया के प्रतिस्पर्धी विचारों और माता-पिता तथा अन्य शिक्षा हितधारकों की आकांक्षाओं को दर्शाते हैं। वे दो मुख्य आयामों से संबंधित हैं: संसाधनों का नियंत्रण और वितरण, और बदलते समाज के लिए मूल्य और विश्वास। शिक्षा के विकल्प काफी कुछ राजनीतिक होते हैं और राजनीतिक एजेंडा में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिलक्षित होते हैं। व्यक्तिगत विचारधारा और परिस्थितियों से उत्पन्न स्थितियों के अलावा, सामाजिक चुनौतियों को समझना तथा सरकार, लोगों और संस्थानों को एक-दूसरे से कैसे जुड़ना चाहिए, यह देशों के बीच भिन्न-भिन्न होता है। यह समझ दृष्टिकोण को प्रभावित करती है कि सरकार को किन नीतियों का अनुसरण करना चाहिए और उनसे किसे लाभ होना चाहिए।

सार्वजनिक शिक्षा के समर्थन पर अनुसंधान उच्च आय वाले देशों से काफी अधिक है। डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, स्पेन, स्वीडन और ब्रिटेन में हाल के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि जब लोगों को अतिरिक्त खर्च के लिए आठ संभावित क्षेत्रों में से एक को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया, तो शिक्षा 28% के लिए शीर्ष विकल्प थी। स्वास्थ्य देखभाल 22% पर दूसरे स्थान पर थीं। जहां 77% लोगों ने स्कूल की पसंद का समर्थन किया, वहीं 60% से अधिक ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में निजी स्कूलों की महत्वपूर्ण भूमिका का विरोध किया।

इस रिपोर्ट के लिए नियुक्त सरकार की भूमिका पर 2016 के अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सर्वेक्षण कार्यक्रम (आईएसएसपी) के विशेष मॉड्यूल डेटा के विश्लेषण ने 10 मध्यम आय वाले देशों सहित 35 देशों के नमूने का उपयोग करके सार्वजनिक शिक्षा समर्थन प्राप्त किया। कुल मिलाकर, 89% वयस्क उत्तर देने वालों ने कहा कि स्कूली शिक्षा प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकारों की है, जबकि 6% ने कहा कि परिवार और 5% अन्य संस्थान (निजी कंपनियां और लाभकारी संगठन; गैर-लाभकारी संगठन, दान और सहकारी समितियां; और धार्मिक संगठन) लेकिन, गैर-सरकारी प्रावधान की सशक्त वकालत करते हुए, भारत (46%),[1] फिलीपींस (63%) और चिली (76%) में उत्तर देने वालों ने सार्वजनिक प्रावधान के लिए सबसे कम समर्थन व्यक्त किया (**चित्र 1**)।

विविध बहस से गैर-सरकारी प्रावधान के पक्ष और विपक्ष में बहस होती है

शिक्षा में गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं के समर्थकों और विरोधियों ने शिक्षा में दक्षता, समानता और समावेश तथा नई खोज को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्राधिकारियों और गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं की क्षमता तथा वैधता के संबंध में अपने मामलों का तर्क दिया। इन मुद्दों को इस नज़रिए से देखा जाता है कि क्या लोग मानते हैं कि शिक्षा एक वस्तु है या बाजार के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली सेवा है और क्या लोगों को शिक्षा का चयन करने में सक्षम होना चाहिए।

क्या गैर-सरकारी कार्यकर्ता शिक्षा में अधिक किफायत लाते हैं? शिक्षा में गैर-सरकारी गतिविधि के समर्थकों का तर्क है कि यह अनिवार्य है क्योंकि सरकार शिक्षा की सभी मांगों को पूरा नहीं कर सकती है। भले ही गैर-सरकारी कार्यकर्ता दान, विश्वास और विचारों, या लाभ से प्रेरित हों, यदि शिक्षण साधनों और सेवाओं की आपूर्ति मांग की जरूरत है, तो बाजार बनेगा ही - यदि पारंपरिक बाजार नहीं है, तो कोई न कोई योजनाबद्ध बाजार होगा। बाजार के माध्यम से, लागत को कम किया जा सकता है।

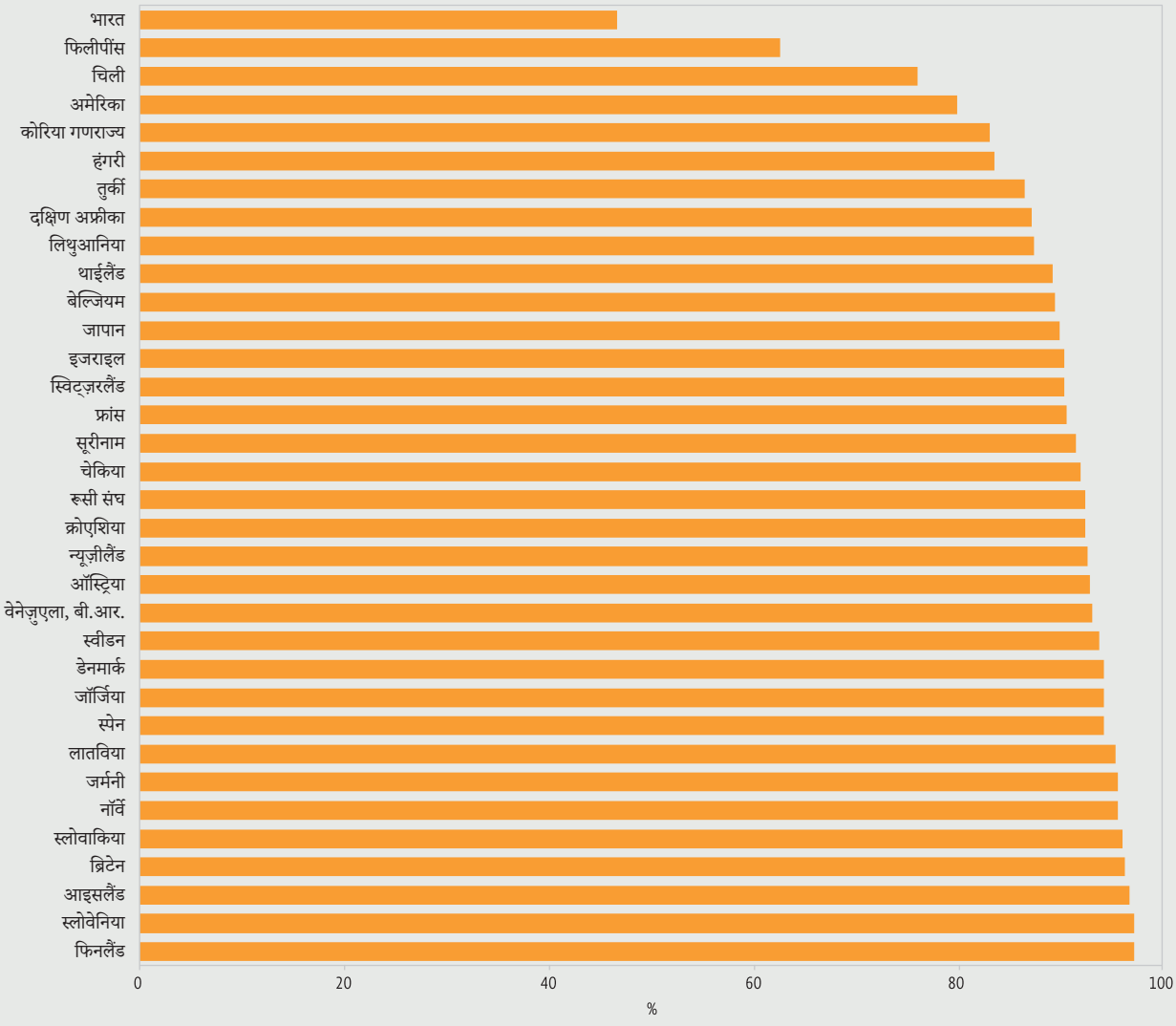
शिक्षा में गैर-सरकारी गतिविधि के विरोधियों का तर्क है कि, यदि लागत को कम करने पर ध्यान दिया जा रहा है, तो उसे पूरी शिक्षा प्रणाली में लागू किया जाना चाहिए तथा सभी स्कूलों, चाहे सरकारी हों या गैर-सरकारी, द्वारा इसे समान रूप से अपनाया जाना चाहिए। यदि यह मामला बनाया जा सकता है कि किसी देश में शिक्षकों को बहुत अधिक भुगतान किया जाता है, तो यह सार्वजनिक नीति को हल करने का मामला होना चाहिए, न कि प्रावधान के मॉडल को बदलने का कारण।

[1] शिक्षा में गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं पर इस रिपोर्ट का क्षेत्रीय संस्करण दक्षिण एशिया को समर्पित होगा।

चित्र 1:

अध्ययन किए गए अधिकांश देशों में, 80% से अधिक शिक्षा के सार्वजनिक प्रावधान के पक्ष में हैं

वयस्कों का प्रतिशत जिन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की है, 2016



जीईएम सांख्यिकी लिंक: https://bit.ly/GEM2021_Summary_fig1

स्रोत: 2016 आईएसएसपी पर आधारित एडलंड और लिंड (2021) ।.

गैर-सरकारी कार्यकर्ता युवा या अयोग्य शिक्षकों को नियुक्त करके लागत कम कर सकते हैं, जो कोई स्थायी समाधान नहीं है। सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों के बीच विश्वसनीय लागत की तुलना करना चुनौतीपूर्ण है। सरकारी स्कूल अधिक वंचित आबादी को शिक्षा उपलब्ध कराते हैं, जिन्हें शिक्षित करना महंगा होता है।

क्या गैर-सरकारी कार्यकर्ता शिक्षा में समानता लाते हैं और सभी को शामिल करते हैं? गैर-सरकारी प्रावधान के समर्थकों का तर्क है कि गैर-सरकारी प्रदाता शिक्षा के अधिकार को पूरा करने में मदद करते हैं। कई संदर्भों में, गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं ने शिक्षा के प्रावधान में मौजूद कमी को पूरा किया है, इसमें प्राय: सार्वजनिक प्रणालियों द्वारा उपेक्षित वंचित समूह शामिल होते हैं। सरकारें प्राय: अनौपचारिक बस्तियों में स्कूल स्थापित करने से हिचकती हैं, जैसा कि पाकिस्तान में है। गैर-सरकारी कार्यकर्ता संकट और आपातकालीन स्थिति में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जैसे कि नेपाल के विनाशकारी 2015 भूकंप के बाद। अल सल्वाडोर में, हिंसा और गिरोहों से पीड़ित शहरी क्षेत्रों में, गैर-सरकारी स्कूलों में दाखिले का औसत राष्ट्रीय औसत से दोगुना है।

जो लोग गैर-सरकारी स्कूलों का विरोध करते हैं, वे स्कूल की पसंद के कारण होने वाली समस्याओं की ओर इशारा करते हैं। यदि माता-पिता मार्गदर्शी विनियमों के बिना अपने मनचाहे स्कूल का चयन कर सकते हैं, तो सबसे अमीर लोग सबसे अच्छे, प्राय: गैर-सरकारी स्कूलों का खर्च उठाने में सक्षम होंगे, जिससे असमानता, वर्ग विभाजन और अलगाव बढ़ जाएगा। माता-पिता को निर्णय लेने के लिए अच्छी जानकारी होना आवश्यक है, लेकिन स्कूल की विशेषताओं के बारे में जानकारी का अभाव होता है या, यदि यह उपलब्ध होती हैं, तो समान रूप से प्रदान नहीं की जाती है, तथा अधिक वंचित आबादी तक इनकी पहुंच कम होती है। इसके अलावा, कई दुर्गम इलाके ऐसे हैं जहां आबादी तक पहुंचना मुश्किल होता है, जहां प्रदाता सेवाएं प्रदान करने के अनिच्छुक हो सकते हैं।

उनमें से कुछ जो सोचते हैं कि शिक्षा के प्रावधान में सरकार की प्राथमिक भूमिका नहीं होनी चाहिए, वे शिक्षा की पाठ्य सामग्री या वांछित स्तर की शिक्षा देने की क्षमता पर निर्णय लेने के उनके अधिकार को चुनौती देते हैं। माता-पिता इस चिंता के कारण अलग और गैर-सरकारी प्रावधान को चुन सकते हैं कि स्थानीय सरकारी स्कूल उस सांस्कृतिक, जातीय, भाषाई या धार्मिक समुदाय के मूल्यों के लिए खतरा है जिसमें वे अपने बच्चे की परवरिश करना चाहते हैं। लेकिन सरकारें यह तर्क दे सकती हैं कि यह समान और सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की उनकी प्रतिबद्धता के विपरीत है और बिना किसी अपवाद के सभी बच्चों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के प्रयास में समान मानकों को लागू करने की उनकी क्षमता में हस्तक्षेप है।

क्या गैर-सरकारी कार्यकर्ता शिक्षा में अधिक नवीनता लाते हैं? शिक्षा में गैर-सरकारी भागीदारी के समर्थकों का दावा है कि यह नयापन बढ़ाने में मदद करता है। कई विचार जिन्होंने शिक्षाशास्त्र की सोच को बदल दिया है, सार्वजनिक शिक्षा प्रणालियों के हाशिये पर या उनके बाहर भी उभरे हैं। सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली बड़ी, केंद्रीकृत नौकरशाही में विकसित हो गई है जो उस आबादी की अनदेखी कर सकती है जिसकी उन्हें सेवा करनी है। एक आम आलोचना यह है कि यह पहल को कुंद करती है, मानक बनाने के लिए बाध्य करती है तथा छात्रों और शिक्षकों को हतोत्साहित करती है।

सार्वजनिक शिक्षा प्रणालियों के लिए नयापन प्रदान करना एक जटिल कार्य है। आकार और माप में बदलने के लिए परिवर्तनों का प्रायोगिक तौर पर परीक्षण करने की आवश्यकता होती है। चुनौतियों में नौकरशाही बाधाएं, संगठनात्मक क्षमता अंतराल, शिक्षक की कमी तथा माता-पिता की प्रेरणा, सीमित वित्तीय साधन और राजनीतिक हस्तक्षेप और विरोध शामिल हो सकते हैं। हालांकि, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली स्वरूप में नयापन लाने की विरोधी नहीं है। और कुछ गैर-सरकारी कार्यकर्ता यह परीक्षण कर रहे हैं कि सार्वजनिक शिक्षा में कुछ नयापन लाया जा सकता है या नहीं।

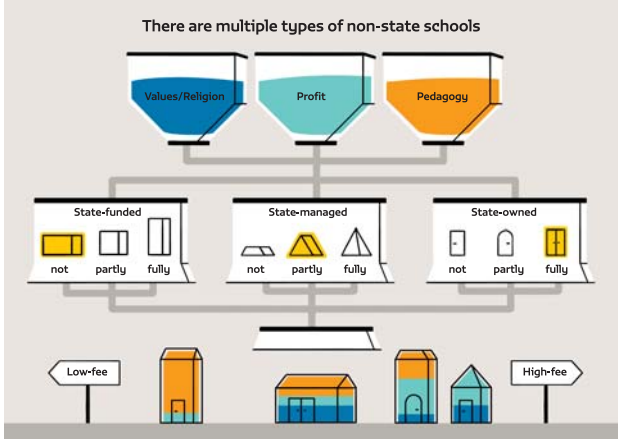
नवीनता पर बहस में प्राय: प्रमुख अवधारणाओं को विरोधाभासी तरीकों से प्रस्तुत करके संदेह उत्पन्न किया जाता है। मानकीकरण को उन लोगों द्वारा बदनाम किया जाता है जिन्हें वे सार्वजनिक शिक्षा प्रणालियों की कठोरता, अनुरूपता और आवश्यकता अनुरूप शिक्षा की कमी के रूप में देखते हैं, लेकिन उन लोगों द्वारा बचाव किया जाता है जो सभी स्कूलों में मानकों को पूरा करने के लिए सामान्य मूल पाठ्यक्रम का समर्थन करते हैं और जो यह मानते हैं कि यह प्राय: निजी प्रदाताओं द्वारा उत्पन्न किया गया प्रतिस्पर्धी दबाव है, जो अनुरूपता की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। तो, क्या मानकीकरण नवीनता को हतोत्साहित करता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन से मानक परिभाषित किए गए हैं। शिक्षा के संगठनात्मक सिद्धांतों के रूप में 'जवाबदेही', 'स्वायत्तता' और 'पसंद' जैसे शब्दों की प्रशंसा और निंदा दोनों की जाती हैं। हालांकि इनमें से किसी भी विचार की उनके गुण-अवगुण के आधार पर जांच की जा सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह गैर-सरकारी और विशेष रूप से निजी शिक्षा प्रावधान की किसी बड़ी भूमिका को उचित ठहराए।

शिक्षा में सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं के बारे में प्रचलित मिथक

इस रिपोर्ट में शिक्षा में सरकारी और गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं के बारे में दस प्रचलित मिथकों पर सवाल उठाया गया है।

मिथक 1.

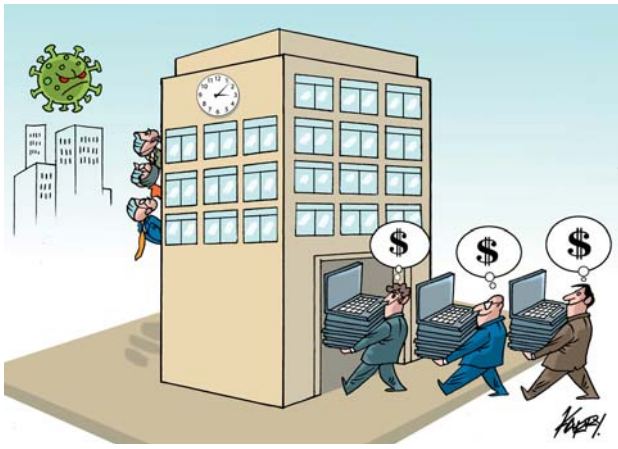
सरकारी और गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं का स्पष्ट रूप से अंतर किया जा सकता है।



शिक्षा में गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं की चर्चा में आम तौर पर दोहरा वर्गीकरण शामिल होता है: सरकारी और निजी स्कूल। व्यवहार में, यह परिदृश्य अधिक जटिल है और अंतर बहुत कम स्पष्ट हैं। गैर-सरकारी कार्यकर्ता अत्यधिक विषम हैं। वे विचारों, मूल्यों, आस्था और रुचियों जैसे विविध कारणों से शिक्षा जगत में प्रवेश करते हैं। कई सरकार के साथ औपचारिक या अनौपचारिक संगठनात्मक व्यवस्था करते हैं, जिसमें अनुबंध और सार्वजनिक-निजी भागीदारी शामिल हैं, जो अंतर करने की रेखाओं को धुंधला करती हैं।

मिथक 2

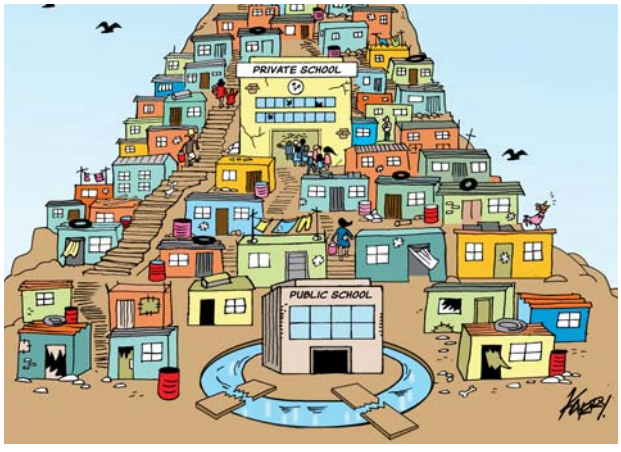
निजीकरण की सीमा ज्ञात है।



गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं की भूमिका में रुझानों का विवरण प्राय: कुल दाखिले में निजी संस्थानों की हिस्सेदारी पर निर्भर करता है। सरकारी स्कूल के शिक्षकों के बारे में देश क्या सोचता है जो स्कूली घंटों के बाद छात्रों को पढ़ाकर अतिरिक्त आय कमाते हैं? कोई शिक्षा प्रणाली कितनी सार्वजनिक है जो पाठ्यपुस्तकों, मूल्यांकन या डेटा प्रबंधन, या यहां तक कि खानपान और परिवहन को आउटसोर्स करती है? क्या किसी लामबंदी के समर्थक द्वारा लिखी गई सरकारी नीति को अभी भी सार्वजनिक माना जाता है?

मिथक 3.

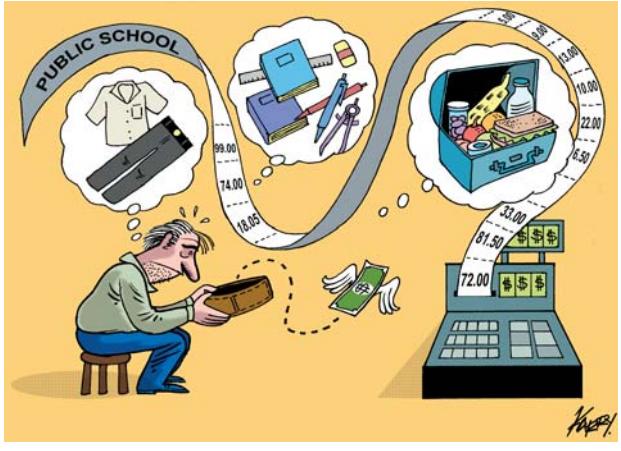
शिक्षा में निजीकरण के लिए निजी क्षेत्र जिम्मेदार है। .



अधिकांश प्राइवेट स्कूल एकल व्यक्ति के स्वामित्व वाले स्कूल हैं। वे सरकारी स्कूलों की उपेक्षा से कम हुई गुणवत्ता को देखते हुए माता-पिता की वास्तविक चिंताओं के कारण उभरे हैं। जब गुणवत्ता में गिरावट स्पष्ट हो गई, तो अमीर और, कुछ हद तक, गरीब परिवारों ने भी सरकारी व्यवस्था को छोड़ दिया, जिससे इसके पक्षकार कम हो गए और परिणामस्वरूप वित्त-पोषण कम हो गया। राजनीतिक नेताओं में प्रभुत्व वर्ग ने बढ़ती असमानता के प्रति अपने नजरिए को बदला तथा सार्वजनिक शिक्षा और इससे लाभान्वित होने वाली वंचित आबादी की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को कम कर दिया।

मिथक 4.

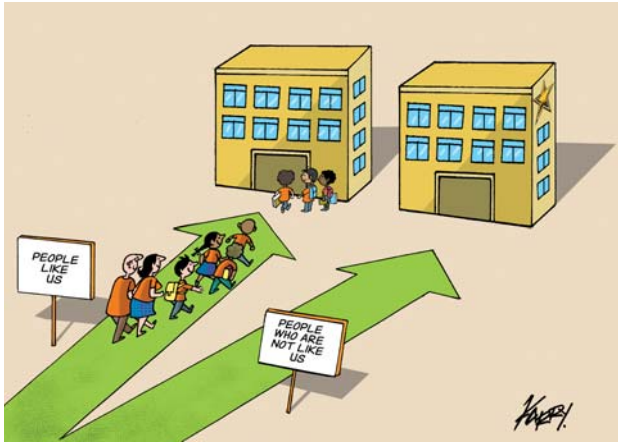
सार्वजनिक शिक्षा न्यायसंगत है



परिवारों को प्राय: छिपी हुई फीस, अपनी जेब से खर्च की गई अनावश्यक राशि और अतिरिक्त खर्च के माध्यम से भरपाई के रूप में उच्च शिक्षा लागत वहन करनी पड़ती है जो सरकारी स्कूल प्रदान नहीं करते हैं। जबकि शिक्षा प्रणालियों की आलोचना करना आम बात है, जिन्होंने गैर-सरकारी प्रदाताओं के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, जो असमानता को बढ़ाते हैं, कई सार्वजनिक शिक्षा प्रणालियां वर्ग भेद और अलगाव को रोकने में विफल रही हैं।

मिथक 5.

माता-पिता गुणवत्ता के बारे में पुख्ता जानकारी के आधार पर स्कूल का चयन करते हैं।

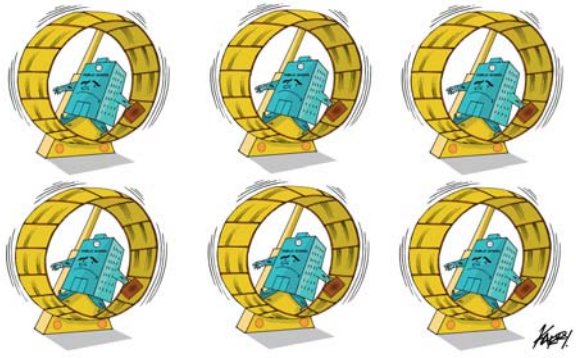


गैर-सरकारी स्कूलों और स्कूल की पसंद के समर्थकों के बीच एक मूलभूत धारणा यह है कि माता-पिता एक उपभोक्ता की तरह सर्वश्रेष्ठ स्कूलों के बारे में जानकारी जुटाते हैं और इसका कुशलता से उपयोग करते हैं। व्यावहारिक तौर पर, अधिकांश देशों में प्रबंधन और संचार के लिए स्कूलों के डेटा का प्रभाव बहुत अधिक भिन्न है। और माता-पिता प्राय: ऐसी जानकारी को अनदेखा कर देते हैं, वे ऐसे स्कूलों का चयन करते हैं जो उन्हें अन्य कारणों से पसंद आते हैं जैसे: धार्मिक आस्था, सुविधा और छात्रों की जनसांख्यिकीय विशेषताएं।

मिथक 6.

प्रतिस्पर्धा से विद्यालय में सुधार होता है।

यह जरूरी नहीं कि प्रतिस्पर्धा से ही स्कूलों में सुधार हो



जवाबदेही और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कुछ लोगों को सुधार करने के लिए प्रेरित करती है। आर्थिक क्षेत्र में, कंपनियां अस्तित्व में बने रहने के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, क्योंकि लाभ अर्जित करके ही वे बनी रह सकती हैं। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इस तरह का उतार-चढ़ाव शिक्षा जगत में कैसे काम करता है। विषय-वस्तु की जटिलता के कारण प्रतिस्पर्धा के प्रणाली पर पड़ने वाले व्यापक प्रभावों को प्रदर्शित करने वाले अध्ययन दुर्लभ हैं, और निष्कर्ष किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। सबसे खराब बात यह है कि प्रतिस्पर्धा गैर-सरकारी स्कूलों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के बजाय माता-पिता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित कर सकती है।

मिथक 7.

निजी स्कूल और विश्वविद्यालय बेहतर हैं।



सरकारी और निजी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण दरों की तुलना स्कूल लीग तालिका के लिए सामान्य साक्ष्य है जैसा कि मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया जाता है और माता-पिता द्वारा समझा जाता है। व्यवहार में, छात्रों की संख्या भिन्न होती है, अच्छे संपन्न, सुशिक्षित और उच्च आकांक्षा रखने वाले माता-पिता द्वारा निजी स्कूल चुनने की संभावना अधिक रहती है। बदले में, निजी स्कूल शीर्ष परिणामों की संभावना को अधिकतम करने के लिए छात्रों की स्क्रीनिंग करने में सक्षम हो सकते हैं। जब ऐसे तथ्यों को नियंत्रित किया जाता है, तो सरकारी और निजी स्कूलों के बीच की खाई को आम तौर पर कम या समाप्त कर दिया जाता है।

मिथक 8.

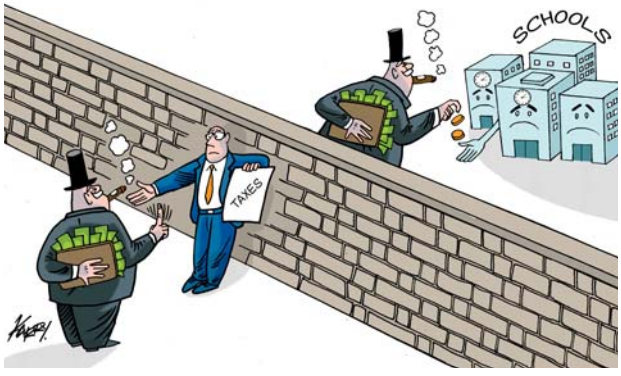
निजी क्षेत्र स्कूल से बाहर की चुनौती का समाधान है।



निजी संस्थानों में दाखिल 350 मिलियन से अधिक प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के साथ, यदि ये छात्र सरकारी शिक्षा प्रणाली में चले गए तो निश्चित रूप से संकट पैदा हो जाएगा। हालांकि, शहरी क्षेत्रों में निजी स्कूल फल-फूल रहे हैं, जहां दाखिले का स्तर पहले से ही सार्वभौमिक है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में काफी हद तक ऐसा नहीं हैं। और निम्न और मध्यम आय वाले देशों में, सबसे अमीर 20% परिवारों के बच्चों के सबसे गरीब 20% परिवारों के अपने साथियों की तुलना में निजी स्कूल में जाने की संभावना 10 गुना अधिक है।

मिथक 9.

निजी क्षेत्र शिक्षा वित्तपोषण में कमी का समाधान है।



आम तौर पर ऐसी बड़ी उम्मीदें लगाई जाती हैं कि निजी क्षेत्र एसडीजी 4 हासिल करने में मदद करने के लिए शिक्षा के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि वह ऐसा करने के लिए तैयार है या सक्षम है। लेकिन यह अन्य योगदान कर सकता है, उदाहरण के लिए कर के माध्यम से, विशेष रूप से निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों में जहां घरेलू राजस्व जुटाने की दर कम है तथा कर चोरी और कर बचाने के अवसर मौजूद हैं। निजी क्षेत्र राष्ट्रीय नियमों के अनुसार कौशल विकास और बाल देखभाल सेवाओं में अहम भूमिका निभा सकता है।

मिथक 10.

विनियम गैर-सरकारी प्रावधान के बारे में सभी चिंताओं को दूर कर सकते हैं।



इस बात पर आम सहमति है कि शिक्षा में गैर-सरकारी गतिविधि को नियंत्रित किया जाना चाहिए। लेकिन विनियम सार्थक रूप से यह नहीं बताते कि समानता और गुणवत्ता प्रणाली को कैसे बढ़ावा दिया जाए। कुछ सरकारें इस बात की निगरानी करती हैं कि क्या धनी परिवारों का निजी स्कूलों में जाना शिक्षा प्रणाली को अलग करता है या घरेलू शिक्षा खर्च असमानता को कैसे बढ़ाता है। कई सरकारें चुनिंदा स्कूल दाखिले की अनुमति देती हैं। कुछ निजी पूरक ट्यूशन या लामबंदी को नियंत्रित करते हैं, जो साझेदारी की आड़ में काफी हद तक छिपा रहता है। कुछ में विनियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के और भी कम संसाधन होते हैं।

लगभग 25 साल पहले अमेरिका में, जब स्कूल की पसंद के आधार पर सार्वजनिक शिक्षा के नए संगठनात्मक रूपों के असमान प्रभावों के प्रमाण सामने आने लगे, तो प्रारंभिक अध्ययन के लेखकों ने निष्कर्षों को दो प्रश्नों के साथ संक्षेप में प्रस्तुत किया: कौन चुनता है? कौन वंचित रह जाता है? (फुलर और एलमोर, 1996)। जैसे-जैसे दुनिया भर में अपनी पसंद का स्कूल चुनने के मशीनी, प्रभावी और परिणामों के अधिक प्रमाण जमा होते गए, *वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट* ने इन सवालों को दुनिया भर के लोगों के सामने रखा। गैर-सरकारी गतिविधि के चार प्रमुख पहलू हैं - प्रावधान, विनियम, वित्तपोषण और प्रभाव – जिनका प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में समाधान किया जाता है, इसके बाद अन्य शिक्षा स्तरों पर इन पहलुओं पर अधिक गहराई से नज़र डालते हैं, जिन पर कम ध्यान दिया जाता है: बचपन शिक्षा, उच्च स्तरीय शिक्षा और तकनीकी, व्यावसायिक और वयस्क शिक्षा।

प्रावधान

गैर-सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ रहा है। दुनिया भर में निजी संस्थानों की हिस्सेदारी में लगभग 10 वर्षों में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई, प्राथमिक शिक्षा में 2002 में 10% से 2013 में 17% तक और माध्यमिक शिक्षा में 2004 में 19% से 2014 में 26% हो गई, लेकिन तब से यह लगभग स्थिर बनी हुई है **(चित्र 2)**।

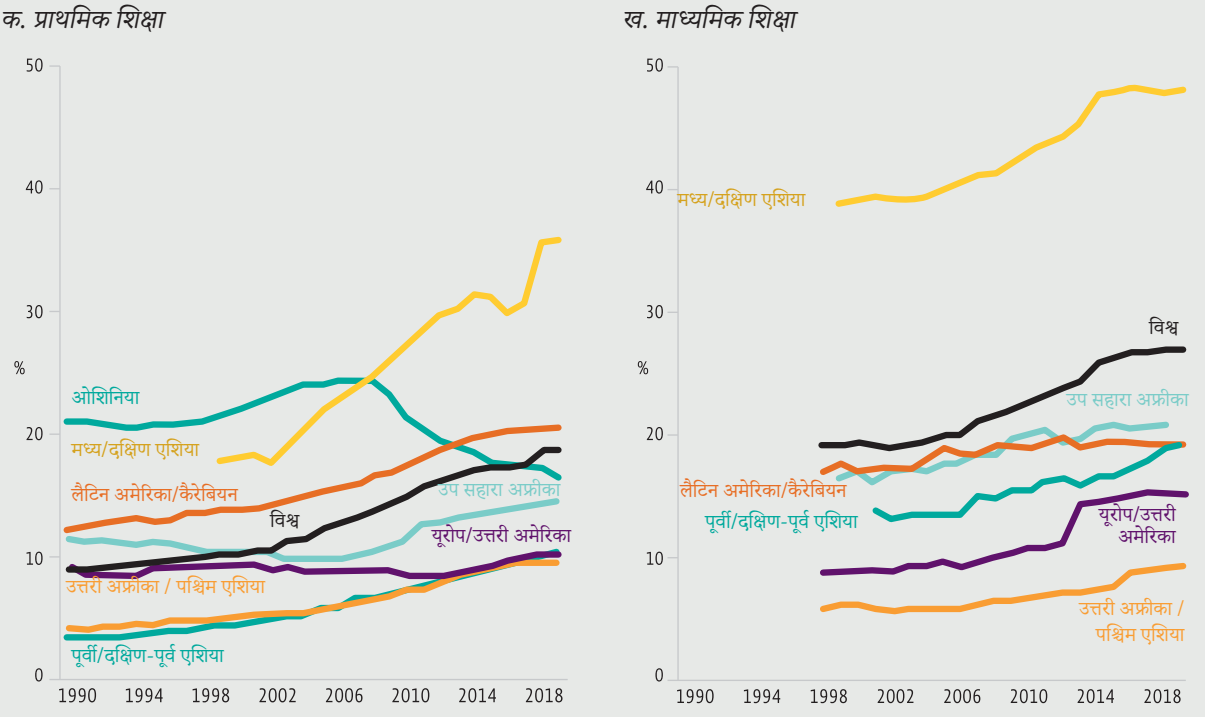
गैर-सरकारी क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए स्वामित्व, प्रबंधन और वित्तपोषण सामान्य मानदंड हैं। सरकार के साथ प्रदाताओं के संबंध, उनकी प्रेरणा और उनकी कीमत का उपयोग उन्हें समूहबद्ध करने के लिए किया जा सकता है। इस रिपोर्ट के विश्लेषण में पाया गया कि आस्था आधारित स्कूल 196 देशों में से 124 में देखे जा सकते हैं। गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) और सामुदायिक स्कूल 196 देशों में से 74 में देखे जा सकते हैं, जो प्राय: आपातकालीन संदर्भ में होते हैं। संयुक्त अरब अमीरात जैसे कुछ संदर्भों को छोड़कर, मुनाफा कमाने वाले स्कूल काफी कम हैं। उप-सहारा अफ्रीका और एशिया में निम्न और मध्यम आय वाले देशों में मामूली कीमत वाले, अधिकतर एक व्यक्ति के मालिकाना अधिकार वाले स्कूलों को कम फीस वाले निजी स्कूलों के रूप में जाना जाता है।

सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में छात्रों का दाखिला और संसाधन भिन्न-भिन्न हैं। कुछ गरीब बच्चों के पास निजी स्कूलों में जाने का विकल्प होता है। शिक्षा के अनुभव की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए, माता-पिता कक्षा के आकार, शिक्षक की गुणवत्ता एवं प्रयास,

चित्र 2:

दक्षिणी एशिया में निजी दाखिले की हिस्सेदारी सबसे अधिक हैं

शिक्षा स्तर के अनुसार निजी संस्थानों में दाखिले का प्रतिशत, 1990-2019



जीईएम सांख्यिकी लिंक: https://bit.ly/GEM2021_Summary_fig2

स्रोत: यूआईएस डेटाबेस।

स्कूल की जवाबदेही, अनुशासन एवं सुरक्षा, शिक्षा की भाषा, धर्म, जातीयता और संस्कृति पर विचार करते हैं। ब्रिटेन में, 18,000 अंग्रेजी स्कूलों के तहत निजी तौर पर प्रबंधित पब्लिक स्कूलों का पब्लिक स्कूलों के साथ विश्लेषण करने में बाद अयोग्य शिक्षकों का एक बड़ा प्रतिशत पाया गया। सरकारी और निजी स्कूल अन्य संसाधनों में भिन्न हो सकते हैं। लैटिन अमेरिका में, निजी स्कूलों में प्रति छात्र कंप्यूटर की औसत संख्या सरकारी स्कूलों की तुलना में दोगुनी है।

अधिकांश प्रमाण बताते हैं कि निजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने और सीखने के लाभ सीमित हैं। 31 निम्न और मध्यम आय वाले देशों के डेटा ने दिखाया कि निजी स्कूल में पढ़ने की अनुमानित साख घरेलू संपत्ति के समायोजन के बाद आधा से दो-तिहाई तक गिर गई। इसके अलावा, जबकि बुनियादी शिक्षा का गैर-सरकारी प्रावधान लघु या मध्यम अवधि की कमी को पूरा कर सकता है, यह अलगाव और असमानता को जन्म दे सकता है। स्वीडन में, 30 में से 29 नगर पालिकाओं में निचले माध्यमिक विद्यालयों को दृढ़ता से अलग किया गया था; 16 में, पृथक्कता काफी हद तक स्कूल की पसंद से प्रेरित थी। जबकि गैर-सरकारी स्कूलों के साथ प्रतिस्पर्धा से सरकारी स्कूलों में सुधार की उम्मीद की जाती है, निजी या अन्य स्कूलों का पास में स्थित होना पब्लिक स्कूल के अधिकारियों के लिए कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं हो सकता है यदि उनके पास कार्रवाई करने के लिए वित्तीय संसाधन या स्वायत्तता नहीं है।

निजी पूरक ट्यूशन लगभग हर जगह मौजूद है। ट्यूशन पूर्वी एशिया और अरब राज्यों के कई देशों में प्रचलित है, यह उन क्षेत्रों में भी फैल रही है जहां यह आम बात नहीं थी, जैसे कि उप-सहारा अफ्रीका और उत्तरी यूरोप। पूरक ट्यूशन की मांग प्रतिस्पर्धी में आगे बने रहने के लिए छात्रों की उच्च स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन हर छात्र के प्रदर्शन पर ट्यूशन का प्रभाव अलग-अलग होता है: कुछ अध्ययनों से सबसे पीछे रहने वालों के लिए छात्रों पर सकारात्मक प्रभावों का पता लगाया गया है, जबकि अन्य अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ट्यूशन का छात्र के प्रदर्शन पर कोई व्यवस्थित सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अलावा, ट्यूशन छात्र और शिक्षक के व्यवहार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करके शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन को कमजोर कर सकता है।

सरकार की भागीदारी के संदर्भ में पाठ्यपुस्तक नीति, खरीद और वितरण अलग-अलग हैं। कुछ देशों में, प्रकाशन मुख्य रूप से सरकार के स्वामित्व वाले और नियंत्रित उद्यमों द्वारा किया जाता है; अन्य में, सरकारी और निजी प्रकाशन की मिश्रित प्रणाली है। स्पेन सहित कई उच्च आय वाले देश पाठ्यपुस्तकों के सृजन को मुख्य रूप से व्यावसायिक प्रदाताओं पर छोड़ देते हैं, जिसमें सरकार दिशानिर्देश प्रदान करने और प्रस्तावों को मंजूरी देने में शामिल होती है। अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों, दाताओं और स्थानीय हितों के बीच सहयोग प्राय: गरीब देशों में स्थानीय प्रकाशन का रूपांतर जटिल बना देता है। उदाहरण के लिए, गैबॉन के पाठ्यपुस्तक उद्योग में एडिसेफ का वर्चस्व है, जो दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक, फ्रांसीसी स्वामित्व वाली हैचेट लिवरे की पाठ्यपुस्तक प्रकाशन शाखा है।

बड़ी प्रकाशन और प्रौद्योगिकी कंपनियों के नेतृत्व में पाठ्य सामग्री को डिजिटल करने पर जोर दिया गया है। शिक्षा प्रकाशन में वैश्विक बाजार में अग्रणी पियर्सन ने 'दुनिया की पाठ्यपुस्तकों और ऑनलाइन शिक्षण सामग्री के सबसे बड़े प्रकाशक' के अपने नारे को बदलकर 'दुनिया की डिजिटल लर्निंग कंपनी' कर दिया है, जिसमें ऑनलाइन स्कूली शिक्षा और मूल्यांकन पर अधिक ध्यान दिया गया। वैश्विक और क्षेत्रीय पाठ्यपुस्तक प्रकाशकों से परे, प्रौद्योगिकी दिग्गजों ने ऑनलाइन शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश किया है, यह रुझान कोविड-19 महामारी के दौरान और सुदृढ़ हुआ है। अमेरिका में शिक्षा प्रौद्योगिकी खरीद प्रक्रिया के अनुभवों के विश्लेषण में पाया गया कि स्कूल जिले और स्कूल आम तौर पर हजारों शिक्षा प्रौद्योगिकी विक्रेताओं द्वारा उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला की बिक्री करने को लेकर खासे उत्साहित थे।

सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अधिक सहायक सेवाओं को आउटसोर्स कर रही है। आउटसोर्सिंग के आलोचकों को आशंका है कि निजीकरण सरकारी सेवाओं और व्यावसायिकता को कमजोर कर सकता है। एक ऑस्ट्रेलियाई विश्लेषण में पाया गया कि सफाई कर्मचारियों के अनुबंध में वृद्धि के कारण ठेकेदारी व्यवस्था का प्रसार हुआ, कम भुगतान करने की घटनाएं बढ़ी, सफाई के घंटों में कमी आई तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों में कमी आई।

शासन और विनियम

गैर-सरकारी शिक्षा प्रदाताओं की व्यवस्था प्राय: खंडों में होती है। सुशासन और प्रभावी नियम अच्छी गुणवत्ता की एक-समान शिक्षा प्रदान करने की सरकारों की क्षमता का मुख्य रूप से निर्धारण करते हैं। 94 देशों में, क्षेत्रीय योजनाओं या कार्यनीतियों में प्रावधान या अन्य सेवा सुपुर्दगी में गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप की परिकल्पना की गई है। कुछ देशों में मंत्रालय या विभाग जिम्मेदारियां साझा करते हैं। विखंडन, समन्वय की कमी और दोहरापन या जिम्मेदारियों की अस्पष्ट अभिव्यक्ति समानता और गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। 83% देशों में शिक्षा मंत्रालय गैर-सरकारी प्रदाताओं के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि 13% के पास विविध प्राधिकार हैं। केवल 39% देशों में शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्तर पर कोई निजी शिक्षा विभाग, प्रभाग या एजेंसी है। शिक्षा मंत्रालयों के बजाय धार्मिक मामले, 22% देशों में आस्था-आधारित स्कूलों के लिए जिम्मेदार हैं - और उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में यह 70% है।

वित्त-पोषण तंत्र का शासन पर प्रभाव पड़ता है। गैर-सरकारी कार्यकर्ता विभिन्न रूपों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं: छात्रों को सहायता (79% देशों में), माता-पिता को सब्सिडी (23%), शिक्षक वेतन या अन्य परिचालन अनुभव (लगभग 70%) और ऋण या उपहार के लिए सहायता (27%)। सरकारी-निजी भागीदारी में प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ-साथ विविध नीति और विनियामक व्यवस्था के बीच विभिन्न स्तर पर संबंध होता है। वित्त-पोषण

व्यवस्था पर किए गए अध्ययनों की समीक्षा में पाया गया कि यह प्रभाव प्राय: नकारात्मक था। 98 अध्ययनों में से कम से कम दो-तिहाई में, सब्सिडी, वाउचर कार्यक्रमों और चार्टर कार्यक्रमों की समानता पर प्रभाव नकारात्मक पाया गया।

विनियमों को शिक्षा में गुणवत्ता और समानता में सुधार करने में मदद करनी चाहिए। लगभग सभी देशों में गैर-सरकारी स्कूलों के दाखिले और संचालन की आवश्यकताओं को निर्धारित करने वाले नियम हैं जिसमें पंजीकरण और लाइसेंस देना शामिल है। 80% देशों में, स्थान की आवश्यकता के संबंध में नियम हैं, जैसे कि भूखंड या भवन का आकार और न्यूनतम कक्षा स्थान। भारत के हरियाणा राज्य में, स्कूलों को स्थापित करने के लिए भवनों को कम से कम 20 वर्षों के लिए स्वामित्व या पट्टे पर लेने की आवश्यकता होती है। एक अन्य राज्य, उत्तर प्रदेश, किसी स्कूल को मान्यता देने के लिए दो मानदंडों का उपयोग करता है: प्रति छात्र न्यूनतम क्षेत्र (9 मीटर^2) और कक्षा का आकार (180 मीटर^2)। विनियमों में पानी और स्वच्छता भी शामिल हैं। 47% देशों से प्राप्त डेटा में, गैर-सरकारी स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय होना आवश्यक है। 74% देशों में छात्र/शिक्षक अनुपात नियंत्रित हैं। लगभग 55% देशों में गैर-सरकारी स्कूलों में दाखिला प्रक्रियाओं से संबंधित नियम हैं, जबकि 67% अनिवार्य शिक्षा में गैर-सरकारी स्कूल की फीस को नियंत्रित करते हैं। आधे से अधिक के पास पाठ्यक्रम पर नियम हैं। पिछले 10 वर्षों में, 21 देशों ने लाभ कमाने और 80 देशों ने शिक्षक के प्रमाणन पर नियम लागू किए हैं।

कमजोर क्रियान्वयन और पर्याप्त जवाबदेही न होना शिक्षा की गुणवत्ता और समानता को कमजोर करती है। नियम लागू होने का मतलब यह नहीं है कि गैर-सरकारी प्रदाता उसका अनुपालन करते हैं। कुछ निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों में, जटिल, महंगी या लंबी पंजीकरण प्रक्रियाएं प्रदाताओं को आधिकारिक मान्यता प्राप्त करने से रोकती हैं। नाइजीरिया की लागोस राज्य सरकार ने 2021 तक 20,000 निजी स्कूलों में से 4 में से केवल 1 को मंजूरी दी थी। कम से कम 27 देशों के आंकड़े से गैर-पंजीकृत स्कूलों का पता चला है। युगांडा गैर-सरकारी स्कूलों को लाइसेंस प्राप्त, पंजीकृत और अपंजीकृत के रूप में वर्गीकृत करता है: 14% प्राथमिक और 13% माध्यमिक स्कूल पंजीकृत नहीं हैं। निरीक्षण की कमी के परिणामस्वरूप अनौपचारिक छात्र दाखिला हो सकता है। बोगोटा, कोलंबिया में, कमजोर छात्रों के लिए स्थापित चार्टर स्कूलों के रियायत स्कूल कार्यक्रम में बिना भेदभाव और निवास निकटता पर आधारित दाखिला नीति थी; वास्तव में, अनौपचारिक रूप से, छात्रों का चयन अकादमिक प्रदर्शन के आधार पर किया गया था।

गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं और मानकों में भिन्नता। व्यावहारिक रूप से हर देश स्कूल निरीक्षण के माध्यम से गैर-सरकारी स्कूल मानकों को लागू करता है। 81% देशों में, यह दायित्व सभी प्रकार के गैर-सरकारी स्कूलों से संबंधित है; 3% में, यह केवल सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों से संबंधित है। इसके अलावा, 81% देशों में बड़े पैमाने के आकलन में गैर-सरकारी स्कूलों की भागीदारी को अनिवार्य करने वाले नियम हैं। उनमें से आधे से अधिक देशों में, यह दायित्व सभी प्रकार के गैर-सरकारी स्कूलों से, जबकि 12% में यह केवल सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों से संबंधित है।

प्रभावी जवाबदेही तंत्र, प्रतिबंध और निवारण तंत्र भी अनुपालन को बढ़ावा दे सकते हैं। सरकार को गुणवत्ता, इनपुट, सुरक्षा और समावेशन के मानकों को लागू करने के लिए शिक्षा प्रदाताओं को जवाबदेह ठहराना चाहिए। यदि गैर-सरकारी स्कूल नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो लगभग सभी देश प्रतिबंध लगाने, स्कूल बंद करने या लाइसेंस वापस लेने की कार्रवाई करते हैं। लगभग 54% देश इस तरह के बंद होने की अवधि को भी नियंत्रित करते हैं। लगभग 90 देशों में शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों के लिए आचार संहिता या आचरण संहिता है, जो प्राय: गैर-सरकारी प्रदाताओं पर लागू होती है।

निजी पूरक शिक्षण को शायद ही कभी नियंत्रित किया जाता है। 48% देशों में निजी शिक्षण अनियंत्रित है। केवल 53 देश इसे शिक्षा कानून में विनियमित करते हैं, जबकि 19 देश इसे केवल वाणिज्यिक कानून के तहत विनियमित करते हैं। 31% देशों में, विनियम ट्यूटरों की आवश्यक योग्यताओं को निर्दिष्ट करते हैं; 10 देशों ने स्पष्ट रूप से शिक्षकों द्वारा ट्यूशन लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन में, 2021 का कानून अनिवार्य स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम पढ़ाने वाली फर्मों को मुनाफा कमाने, पूंजी जुटाने और नए लाइसेंस जारी करने से रोकता है। प्रचालन जारी रखने के लिए कंपनियों को गैर-लाभकारी बनने की जरूरत है। सरकार ने निजी ट्यूटरिंग कंपनियों को नियंत्रित करने और निगरानी के लिए विशेष रूप से एक विभाग की स्थापना की है।

वित्त

सरकारों के निर्णय इस बात को लेकर भिन्न होते हैं कि गैर-सरकारी प्रदाताओं को क्या और कैसे निधियां दी जाएं। कनाडा में, सरकार 30% निजी लेकिन 94% पब्लिक स्कूल खर्च को कवर करती है। नीदरलैंड में, सभी स्कूल, वर्ग की परवाह किए बिना, कर्मचारियों के लिए ब्लॉक अनुदान एवं परिचालन लागत तथा वंचित सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले और विशेष शिक्षा की जरूरत वाले छात्रों के लिए अतिरिक्त धन प्राप्त करते हैं। 2000 के बाद से, चिली, हंगरी, स्वीडन और ब्रिटेन सहित कई देशों ने आश्रित निजी स्कूलों के दाखिले के प्रतिशत में वृद्धि महसूस की है, जो सरकार से अपने वित्त-पोषण का कम से कम 50% प्राप्त करते हैं।

सरकारें गैर-सरकारी स्कूल के केवल कुछ व्यय का वित्तपोषण करती हैं। बांग्लादेश में, 16,000 से अधिक गैर-सरकारी माध्यमिक स्कूल और 7,600 मदरसे, जो कुल मिलाकर 96% छात्रों का दाखिला करते हैं, शिक्षक वेतन के लिए मासिक भुगतान प्राप्त करते हैं। लेकिन हैती, जहां 85% प्राथमिक स्कूल गैर-सरकारी हैं, उसमें वेतन की लागत शामिल नहीं है। भारत में, 2019/20 में केवल 6% प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को शिक्षक के वेतन के लिए अनुदान प्राप्त हुआ।

इंडोनेशिया में, मदरसों और इस्लामिक बोर्डिंग स्कूलों, जिन्हें पेसेंट्रन के रूप में जाना जाता है और सभी निजी स्कूलों का 35% हैं, को कुछ वित्त-पोषण प्रणाली तंत्र से बाहर रखा गया है।

कुछ सरकारें गैर-सरकारी स्कूलों में वंचित छात्रों के दाखिले का समर्थन करती हैं। भारत में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों को निम्न-आय वाले परिवारों के बच्चों को कक्षा 1 में 25% सीटें प्रदान करना आवश्यक था; बदले में, सरकार ने उनकी ट्यूशन लागत की प्रतिपूर्ति की। इसके विपरीत, कोटे डी आइवर ने निष्पक्षता नहीं बरती, जहां सब्सिडी वाले माध्यमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या 2010/11 और 2017/18 के बीच चौगुनी हो गई।

परिवारों को व्यापक बोझ और कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ता है। सकल घरेलू उत्पाद के भाग के रूप में, उच्च आय वाले देशों में घरेलू शिक्षा खर्च 0.3% और निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 1% है। यह अल सल्वाडोर में सकल घरेलू उत्पाद का 1.2%, मोरक्को में 1.5%, भारत में 1.8% और घाना में 2.5% है। जबकि अर्जेंटीना, कोस्टा रिका, फिलीपींस और जाम्बिया में सबसे गरीब 20% परिवार शिक्षा पर व्यावहारिक रूप से कुछ भी खर्च नहीं करते हैं, सबसे अमीर 20% सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% और 1.7% के बीच खर्च करते हैं।

सार्वजनिक शिक्षा प्राय: मुफ्त नहीं होती है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में लगभग एक-तिहाई घरेलू खर्च पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के परिवारों से आता है। ग्वाटेमाला और पाकिस्तान में निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के परिवार लगभग 80% खर्च उठाते हैं; चीन और केन्या में पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के परिवारों का खर्च लगभग 60% खर्च वहन करते हैं। संयुक्त गणराज्य तंजानिया के ग्रामीण क्षेत्रों में, तीन-चौथाई से अधिक परिवार प्राथमिक स्कूल के योगदान को अनिवार्य मानते हैं, यह देखते हुए कि योगदान में देरी होने पर बच्चों को दंडित किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में, माता-पिता का योगदान स्कूलों के बीच असमानता को बढ़ाता है।

कई परिवारों के लिए निजी पूरक ट्यूशन एक बड़ा खर्च है। चीन में, परिवारों ने 2017 में अपने कुल शिक्षा व्यय का लगभग एक-तिहाई हिस्सा स्कूल के बाहर खर्च करने के लिए रखा, जिसमें 17% ग्रामीण परिवारों से लेकर 42% शहरी परिवार शामिल थे। मिस्र में, प्रति व्यक्ति औसत खर्च के भाग के रूप में, सामान्य माध्यमिक शिक्षा में छात्रों के बीच, सबसे अमीर पांच समान क्विंटल परिवारों ने निजी पाठों पर 51% और सबसे गरीब ने 29% खर्च किया। म्यांमार में, ट्यूशन पर कुल घरेलू शिक्षा खर्च का 42% खर्च किया जाता है।

निजी प्रदाता जेब से किए गए घरेलू खर्च पर निर्भर करते हैं। अधिकांश निजी माध्यमिक स्कूलों को अपने राजस्व का कम से कम 80% उच्च-मध्यम और उच्च-आय वाली 51 शिक्षा प्रणालियों में से 28 में फीस से प्राप्त होता है। निम्न और निम्न-आय वाले देशों में, गरीब माता-पिता निजी स्कूल के खर्चों से निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियाँ अपनाते हैं। विश्व स्तर पर, छह में से एक परिवार स्कूल की फीस चुकाने के लिए बचत करता है, जबकि लगभग 8% परिवार उधार भी लेते हैं। हैती, केन्या, फिलीपींस और युगांडा में, 30% या अधिक परिवार स्कूल फीस के लिए उधार लेते हैं।

कोविड-19 से निजी स्कूल का वित्त-पोषण काफी हद तक प्रभावित हुआ है। महामारी ने विशेष रूप से स्कूल की फीस पर निर्भर रहने वाले निजी स्कूलों को प्रभावित किया। नाइजीरिया ने निजी स्कूल के शिक्षकों को भुगतान करने के लिए कम ब्याज वाले ऋण के साथ एक प्रोत्साहन पैकेज शुरू किया। घाना में, निजी स्कूलों को छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए एक सामान्य कार्यक्रम के भाग के रूप में समर्थन मिला। वियतनाम ने निजी स्कूल के शिक्षकों को कवर करने के लिए नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों का विस्तार किया। पनामा में, 35% से 40% माता-पिता मासिक शुल्क किस्त का भुगतान नहीं कर सके। इक्वाडोर में, पब्लिक स्कूलों के दाखिले में 6.5% या 120,000 छात्रों की वृद्धि हुई, जो निजी स्कूलों से चले गए।

निजी शिक्षा के वित्तपोषण के लिए सहायता के उपयोग पर बहस होती है। लगभग 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शिक्षा पोर्टफोलियो में से, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने निजी स्कूल श्रृंखलाओं को 15% आवंटित किया, लेकिन नागरिक समाज संगठनों के दबाव के बाद 2019 में शुल्क वसूलने वाले निजी स्कूलों में अपने निवेश को रोक दिया। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन ने एक निजी क्षेत्र की कार्यनीति विकसित की, लेकिन इसकी वार्ता के दौरान विपक्ष ने मुख्य शिक्षा सेवाओं के लाभ के प्रावधान के पक्ष में समर्थन करने के लिए अपने धन के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाली शर्त का इस्तेमाल किया।

दानकर्ता सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ प्रयोग कर रहे हैं। नकदी संकट से जूझ रही सरकारों ने मिस्र, फिलीपींस और दक्षिण अफ्रीका में सार्वजनिक शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार और विस्तार के लिए निजी पूंजी जुटाई है। कुछ दानदाताओं ने इस तरह की साझेदारी के माध्यम से वित्तपोषण जुटाने के प्रोत्साहन के रूप में अपने धन का उपयोग करने पर ध्यान दिया है। लेकिन इस बात को लेकर चिंता है कि जो सरकारें साझेदारी को डिजाइन, कार्यान्वित और नियंत्रित कर सकती हैं, वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक खरीद का उपयोग करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकती हैं।

शिक्षा में परोपकारी और कॉर्पोरेट गतिविधियों का वित्तीय योगदान बहुत कम है। इस धारणा के बावजूद कि परोपकारी संस्थाएं शिक्षा पर खर्च की जाने वाली राशि में वृद्धि कर रही हैं, यह अपेक्षाकृत बहुत कम बनी हुई है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) की एक पहल, नेटवर्क ऑफ़ फ़ाउंडेशन्स वर्किंग फ़ॉर डेवलपमेंट में 143 फ़ाउंडेशन द्वारा परोपकारी दान के व्यवस्थित विश्लेषण का एक अनुमान लगाया गया जिसके अनुसार 2013 से 2015 तक तीन वर्षों में शिक्षा को 2.1 बिलियन अमेरीकी डॉलर प्राप्त हुए। यह सभी परोपकारी दान के 9% के बराबर था।

प्रभाव

शिक्षा में गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं की भूमिका पर बहस के मूल में दक्षता, नवीनता और समानता के बारे में तर्क हैं। वाद-विवाद को प्राय: कटुता और अविश्वास के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह विश्व संघर्ष के दो बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण हैं। विभिन्न कार्यकर्ता समूह गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं की ठोस भूमिका के लिए उसके पक्ष या विपक्ष में जनमत और शिक्षा नीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। उनके साधन पक्ष-समर्थन और पैरवी नेटवर्क, अनुसंधान और वित्त-पोषण हैं, जो प्राय: वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से जुड़ा होता है। राजनीतिक विचारों और आर्थिक हितों की इस प्रतिस्पर्धा में, जहां कार्यकर्ता अपनी बात के समर्थन में वैध और नाजायज साधनों का उपयोग करते हैं, चुनौती सार्वजनिक शिक्षा नीति प्रक्रिया की पारदर्शिता और अखंडता को बनाए रखने और निहित स्वार्थों को दूर रखने की है।

अधिकांश कार्यकर्ता समूह शिक्षा में गैर-सरकारी प्रदाताओं पर एक-समान विचार नहीं रखते हैं। नागरिक समाज संगठन प्राय: आलोचनात्मक होते हैं, शिक्षा में निजीकरण और वस्तुकरण पर चिंता व्यक्त करते हैं और तर्क देते हैं कि शिक्षा को लोकतांत्रिक नियंत्रण में रहना चाहिए। फिर भी अधिकार-आधारित अभियान के भीतर, जैसे कि वैश्विक शिक्षा अभियान, सदस्य अपने देशों में वास्तविकता से प्रभावित अधिक सूक्ष्म विचार रखते हैं। इस रिपोर्ट के लिए किए गए सदस्यों के एक सर्वेक्षण में, 43% ने लाभ के प्रावधान के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया लेकिन 12% ने समर्थन किया; सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर, हिस्सेदारी 41% और 20% थी, शेष के बारे में मिश्रित दृष्टिकोण व्यक्त किया गया था।

ग्लोबल एडवोकेसी नेटवर्क ने निजीकरण और व्यावसायीकरण को शिक्षा के अधिकार के लिए खतरा बताया है। यह परिप्रेक्ष्य सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करने और शिक्षा में निजी भागीदारी को नियंत्रित करने के लिए राज्यों के मानवाधिकार दायित्वों पर आबिदजान सिद्धांतों में व्यक्त किया गया है। 2018 में, 10 केन्याई नागरिकों ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) के लिए स्वतंत्र जवाबदेही तंत्र, अनुपालन सलाहकार लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि ब्रिज इंटरनेशनल अकादमियां, जो एक लाभकारी श्रृंखला है, पाठ्यक्रम, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा और श्रम मानकों का उल्लंघन कर रही थीं। 2020 में, आईएफसी ने स्कूल श्रृंखलाओं में निवेश को रोक दिया, जबकि विश्व बैंक के स्वतंत्र मूल्यांकन समूह ने निजी स्कूलों में निवेश का मूल्यांकन शुरू किया।

कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों से गैर-सरकारी प्रदाताओं को दी जाने वाली सहायता और संसाधन एजेंडा को प्रभावित करते हैं। जिन उपायों के माध्यम से विश्व बैंक नीति निर्माण को प्रभावित करता है, उनमें निजी क्षेत्र की भागीदारी पर एक मॉड्यूल है, जिसे बेहतर शिक्षा परिणामों के लिए सिस्टम दृष्टिकोण के तहत सीखने को बढ़ावा देने के लिए 13 सबसे महत्वपूर्ण नीति क्षेत्रों में से एक माना जाता है। इसने 10 में से 9 देशों में निजी प्रावधान विस्तार करने की सिफारिश की है। यूनिसेफ द्वारा होस्ट किया गया एजुकेशन आउटकम फंड प्रभाव डालने वाले निवेशकों को परिणाम-आधारित वित्तपोषण परियोजनाएं लागू करने के लिए आकर्षित करता है, जिनका शिक्षा में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से लाभान्वित होने वाले संगठनों में आर्क शामिल है, जिसका विस्तार इंग्लैंड में पब्लिक स्कूलों के संचालन से लेकर लाइबेरिया और दक्षिण अफ्रीका सहित देशों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की सलाह देने और लागू करने में मदद करने के लिए किया जाता है।

फाउंडेशन की स्थिति उस भूमिका से भिन्न है जो उनके विचार में गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं द्वारा निभाई जानी चाहिए। कॉर्पोरेट और परोपकारी फाउंडेशन के विविध कार्यकलापों ने उन्हें एक समूह के रूप में वर्गीकृत करना कठिन बना दिया है। फाउंडेशनों की प्राय: किसी विशेष दिशा में नीति को प्रभावित करने का प्रयास करने के लिए आलोचना की जाती है। परोपकारी लेमन फाउंडेशन ने कई परामर्शों के बाद ब्राजील में राष्ट्रीय शिक्षण मानकों को प्रस्तुत करने में मदद की।

सार्वजनिक शिक्षा का समर्थन करने के प्रयासों में शिक्षक संघ सबसे आगे रहे हैं। यूनियनों ने शिक्षा के अवांछित व्यापारीकरण और सार्वजनिक सेवाओं के आउटसोर्सिंग के माध्यम से सार्वजनिक शिक्षा को कमजोर करने के प्रयासों को प्रभावी ढंग से उजागर किया है। एजुकेशन इंटरनेशनल, शिक्षक संघों का एक संघ, यह सवाल करता रहा है कि क्या लैटिन अमेरिका में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का व्यापक उपयोग, उदाहरण के लिए कोस्टा रिका और डोमिनिकन गणराज्य में, समान उद्देश्यों की सेवा करने वाले सार्वजनिक संस्थानों के लिए नुकसानदायक है। लेकिन कुछ अवसरों पर, सार्वजनिक शिक्षा को सुदृढ़ करने के प्रयासों को कमजोर करने के लिए संघ की कार्यनीति की आलोचना की गई है।

व्यवसाय मानव पूंजी के संदर्भ में शिक्षा सुधार पर अपना पक्ष रखते हैं। जापान बिजनेस फेडरेशन ने दुनिया भर में शक्तिशाली आर्थिक लॉबी की तरह शिक्षा नीति की सिफारिशें की हैं जो आधुनिकीकरण और 21वीं सदी के कौशल के लिए अपील करती है। कुछ ने नियोक्ताओं की भर्ती और प्रशिक्षण प्रथाओं के विपरीत सिफारिशों की आलोचना की है। वैश्विक शिक्षा व्यापार गठबंधन शिक्षा को राजनीतिक महत्व देने के लिए अपने सदस्यों की विशेषज्ञता, नेतृत्व और संसाधनों हेतु अपील करता है। आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक शिक्षा के लिए सबसे अच्छा समर्थन यह होगा कि कर बचाने और कर चोरी के खिलाफ अभियानों के साथ वास्तव में जुड़ा जाए। इस बात पर भी चिंता व्यक्त की गई है कि कैसे शिक्षा टेक्नोलॉजी फर्में सरकारी उत्पादों को बेचने के लिए बिक्री तकनीकों का इस तरह से उपयोग करती हैं, जो जनता की भलाई के लिए नहीं होती हैं। इन फार्मों ने कोविड-19 संकट और दूरस्थ शिक्षा में बदलाव के दौरान अपने इन प्रयासों को तेज कर दिया।

प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा

गैर-सरकारी कार्यकर्ता 3 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी हैं। 33 उच्च आय वाले देशों में, 2018 में कुल दाखिले में निजी संस्थानों की भागीदारी 57% थी। ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में लाभ अर्जित करने के लिए निजी क्षेत्र मुख्य रूप से जिम्मेदार है। जर्मनी में, 2017 में 73% दाखिला निजी संस्थानों में हुआ था, लेकिन केवल 3% प्रदाता लाभ कमाने वाले थे। 33 मध्यम-आय वाले देशों में, गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं की 3 साल से कम उम्र के बच्चों के दाखिले में 46% हिस्सेदारी थी, जो रूसी संघ में शून्य के करीब से लेकर तुर्की में 100% तक थी। अल सल्वाडोर सहित केवल कुछ ही देश व्यापक सरकारी प्रावधान की ओर उन्मुख हुए हैं। कोलंबिया, ग्वाटेमाला और पेरू सहित लैटिन अमेरिकी देशों ने छोटे पैमाने पर, समुदाय-आधारित प्रारंभिक बाल देखभाल कार्यक्रमों को अपनाया है। अमीर देशों में नियोक्ता-आधारित प्रावधान अपेक्षाकृत आम बात है, जो गरीब देशों में धीरे-धीरे उभर रहा है। एक प्रमुख चुनौती यह है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार की हिस्सेदारी केवल 30% है।

बुनियादी शिक्षा की तुलना में गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं की भागीदारी प्री-प्राइमरी में काफी अधिक है। 2000 और 2019 के बीच, प्री-प्राइमरी शिक्षा दाखिले में निजी संस्थानों की हिस्सेदारी 28.5% से बढ़कर 37% हो गई, जो पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में 55% तक पहुंच गई। चीन में 'वॉकिंग ऑन टू लेग्स' नीति के तहत निजी संस्थानों की हिस्सेदारी 31% से बढ़कर 57% हो गई। वियतनाम में, निजी दाखिले का हिस्सा 2003 में 60% से घटकर 2014 में 12% हो गया। यूक्रेन सहित पूर्वी यूरोपीय देशों में हिस्सेदारी 1% से कम, कैरिबियन में 95% से अधिक (जैसे एंटीगुआ और बारबुडा) है और प्रशांत, जहां प्रावधान या तो समुदाय-आधारित (जैसे वानुअतु) या धार्मिक मिशन (जैसे समोआ) से जुड़ा हुआ है। अल्जीरिया और मिस्र के नेतृत्व में उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया, वह क्षेत्र है जिसने प्री-प्राइमरी शिक्षा दाखिले में निजी संस्थानों की हिस्सेदारी में 2000 में 53% से 2019 में 36% तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की। इसके विपरीत, 2000 और 2018 के बीच, इज़राइल में निजी संस्थानों की हिस्सेदारी 5% से बढ़कर 36% और कुवैत में 26% से बढ़कर 45% हो गई।

गैर-सरकारी प्री-प्राइमरी प्रावधान की लागत सबसे गरीब लोगों के लिए बहुत अधिक हो सकती है। घरेलू सर्वेक्षणों से पता चलता है कि प्रशासनिक आंकड़ों ने सात उप-सहारा अफ्रीकी देशों में से छह में गैर-सरकारी दाखिले की हिस्सेदारी को औसतन 20 प्रतिशत अंकों से कम करके आंका। गैर-सरकारी प्रावधान ने मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में मांग को पूरा किया है, जहां ऐसी सेवाएं आम तौर पर उपलब्ध होती हैं, और जिनका खर्च अमीर परिवार उठा सकते हैं। वार्षिक घरेलू खपत के भाग के रूप में, निजी प्री-प्राइमरी शिक्षा में सबसे अमीर परिवार का प्रतिशत 6% और घाना में सबसे गरीब परिवार का प्रतिशत 17% है; इथियोपिया में समकक्ष 4% और 21% हैं।

गैर-सरकारी प्रावधान शासन और विनियम को चुनौती देते हैं। गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं की अधिक संख्या शासन को जटिल बनाती है। कंबोडिया में सामुदायिक प्री-स्कूलों के लिए अलग नियम और व्यवस्था है। श्रीलंका में, बहुक्षेत्रीय विनियामक ढांचा न होने का अर्थ है कई मंत्रालयों (शिक्षा, स्वास्थ्य, और महिला एवं बाल मामले) और प्रांतीय परिषदों के कार्यक्षेत्र का दोहरापन है। लागोस, नाइजीरिया में यह संभावना कि राज्य शिक्षा मंत्रालय किसी निजी प्री-स्कूल का निरीक्षण करेगा कि क्या वे कम शुल्क (48%) की तुलना में उच्च शुल्क (68%) लेते हैं। नैरोबी, केन्या में, धार्मिक, दान या लाभकारी स्कूलों की तुलना में सामुदायिक स्कूलों का अधिक बार निरीक्षण किया जाता है।

गैर-सरकारी प्रदाताओं की गुणवत्ता अत्यधिक परिवर्तनशील है। कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों में, निजी शिक्षक कम तैयार होते हैं और उनके पास सार्वजनिक क्षेत्र के साथियों की तुलना में कम पेशेवर विकास के अवसर होते हैं। केवल 8% निजी लेकिन 75% सार्वजनिक किंडरगार्टन शिक्षक घाना शिक्षा सेवा के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेते हैं, क्योंकि निजी शिक्षकों के लिए कोई न्यूनतम आवश्यकताएं नहीं हैं। गैर-सरकारी प्रि-स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का उपयोग, जैसा कि ब्राजील में है, विकास की दृष्टि से उपयुक्त पाठ्यक्रम और गुणवत्ता की लोकप्रिय धारणाओं के बीच तनाव का एक उदाहरण है।

कुछ निम्न और मध्यम आय वाले देशों में गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाएं होती हैं जो प्रशासनिक आवश्यकताओं से परे होती हैं। जमैका में, जहां प्रावधान मुख्य रूप से गैर-सरकारी हाथों में है, शिक्षा मंत्रालय को योग्य निरीक्षकों की आवश्यकता होती है; अन्य कर्मचारी मासिक निगरानी के लिए साइट का दौरा करते हैं जिसमें 12 राष्ट्रीय मानकों के आधार पर बच्चों, शिक्षकों, माता-पिता, देखभाल करने वालों और समुदाय के सदस्यों के बीच वार्ता तथा संबंध शामिल होते हैं। फिलीपींस सरकार द्वारा मान्य फिलीपीन बाल विकास जांच-सूची के माध्यम से राष्ट्रीय मानकों और दक्षताओं की निगरानी की जाती है।

गैर-सरकारी कार्यकर्ता ईसीसीई में नवीनता की वकालत करते हैं। ऐतिहासिक रूप से, प्रतिबद्ध शिक्षाविदों ने बाल-केंद्रित शिक्षा के अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए औपचारिक सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के बाहर या या उसकी दिशा में काम किया। अकादमिक शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक बाल शिक्षा कार्यक्रमों की दीर्घकालिक प्रभावशीलता की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिससे सार्वजनिक अधिकारियों को ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। गैर-सरकारी कार्यकर्ता स्कूल न जाने वाले बच्चों जैसे, चिली में कारागार में माताओं के साथ काम करते हैं, फिलीपींस में गरीब कामकाजी माता-पिता और रोमानिया में संस्थानों में बच्चों की वकालत करते हैं। बर्नार्ड वैन लीयर फाउंडेशन, आगा खान फाउंडेशन और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जैसे संगठनों ने ईसीसीई के लिए समर्थन जुटाया है और उनकी वकालत की है।.

उच्च स्तरीय शिक्षा

लगभग सभी देश सरकारी और गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं के सहयोग से उच्च स्तरीय शिक्षा प्रावधान सुनिश्चित करते हैं। लगभग 33% उच्च स्तरीय शिक्षा छात्र विश्व स्तर पर निजी संस्थानों में नामांकित हैं, जिनमें मध्य और दक्षिणी एशिया तथा लैटिन अमेरिका और कैरिबियन की सबसे अधिक हिस्सेदारी है। गैर-सरकारी प्रावधान में वृद्धि विभिन्न मांगों को पूरा करती है। धर्म या संस्कृति-उन्मुख संस्थान इतिहास और परंपरा से जुड़े होते हैं, जो 'अलग' तरह की शिक्षा की मांग को पूरा करते हैं। उत्कृष्ट संस्थान 'बेहतर' शिक्षा की मांग को पूरा करने के लिए प्राय: अधिक संपन्न लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। अंत में, छोटे, गैर-संप्रदाय संस्थानों ने हाल ही में कम सार्वजनिक बजट के संदर्भ में 'व्यापक' उच्च स्तरीय शिक्षा की मांग को पूरा किया है।

गैर-सरकारी संस्थानों का प्रणाली की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। कम शुल्क लेने वाले संस्थान अध्ययन के केवल कुछ क्षेत्रों को कवर करते हैं, जो अधिकतर व्यावसायिक उन्मुख होते हैं। भारत में, लगभग 40% निजी कॉलेज केवल एक ही क्षेत्र की पूर्ति करते हैं, आम तौर पर शिक्षा। गैर-सरकारी संस्थानों के शैक्षणिक कर्मचारियों के पूर्णकालिक होने की संभावना कम है - 20% से कम सेनेगल में हैं - और वे अक्सर सार्वजनिक संस्थानों के प्रोफेसर हैं। मलेशिया में, छोटे और नए गैर-सरकारी संस्थानों में 80% कर्मचारी बिना पहचान बताए दूसरी नौकरी करते हैं। लाभ केंद्रित होने के कारण अतिरिक्त गुणवत्ता चुनौतियां पैदा होती हैं जो बाजार आधारित होती हैं और अकादमिक सुधार की तुलना में प्रतिलाभ की प्राथमिकता से जुड़ी होती हैं।

गैर-सरकारी प्रावधान समानता की समस्या को बढ़ाते हैं। उच्च-मध्यम-आय वाले देशों में, कुल दाखिले में गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हिस्सा व्यापक रूप से असमानता के साथ जुड़ा हुआ है। उरुग्वे में, गैर-सरकारी संस्थानों में 75% से अधिक छात्र निकाय सबसे अमीर पांच समूहों से आते हैं, जबकि सार्वजनिक संस्थानों में यह 40% से कम है। फिर भी, गैर-सरकारी संस्थान बाहर निकाले जाने के जोखिम वाले समूहों तक पहुंच प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। सऊदी अरब में, उन्होंने केवल महिला के लिए पाठ्यक्रम बनाकर महिलाओं तक शिक्षा का विस्तार किया है, जबकि मलेशिया में वे जातीय चीनी समुदाय तक पहुंच प्रदान करते हैं और भारतीयों को सार्वजनिक संस्थानों में जातीय कोटा से प्रतिबंधित किया गया है। फिर भी, इस तरह के अलग प्रावधान सामाजिक एकता के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

कानूनी ढांचे गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं के सरकारी विचारों को प्रतिबिंबित करते हैं। सख्त नियम अविश्वास से जुड़े होते हैं, जबकि गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं के अधिक सकारात्मक विचार मान्यता, निगरानी और यहां तक कि सार्वजनिक वित्त-पोषण की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। कुछ देशों में, लाभ अर्जित करने वाले संस्थान सख्त दिशानिर्देशों के अधीन हैं - उन्हें पूरी तरह से गैरकानूनी घोषित किया जा सकता है, जैसे कि अर्जेंटीना और चिली में, या बजट आवंटन पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि फिलीपींस में निवेश पर प्रतिलाभ की 10% की सीमा तय है। कुल मिलाकर, गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों ने भ्रामक व्यावसायिक प्रथाओं में लगे या निम्न-गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थानों को बंद करने में देशों की मदद की है। 2017 में, पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग ने देश में संचालित 153 अवैध संस्थानों की पहचान की। लेकिन गैर-सरकारी संस्थानों को मान्यता देने और निगरानी करने के लिए संसाधनों की अक्सर कमी होती है।

समानता को बढ़ावा देने वाले नियम प्रशासनिक नियमों की तुलना में कम सामान्य हैं। उच्च स्तरीय शिक्षा तक वंचित समूहों की पहुंच में सुधार के लिए बनाए गए कोटा या विशेष प्रवेश मानदंड हमेशा गैर-सरकारी प्रदाताओं को नहीं मिलते हैं। वे कब आवेदन करते हैं, जैसा कि भारत में होता है, यह आमतौर पर केवल उन संस्थानों के लिए होता है जो सार्वजनिक धन प्राप्त करते हैं। अपवाद स्वरूप गैर-सरकारी संस्थानों को कुछ छात्रों को अनुदान या छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए बाध्य करना शामिल है, जैसे कि बोलीविया और इक्वाडोर में है, और छात्र की फीस को सीमित करना, जैसा कि अज़रबैजान और केन्या में है।

गैर-सरकारी संस्थानों के वित्तपोषण के तौर-तरीकों में महत्वपूर्ण गुणवत्ता और समानता शामिल है। अधिकांश गैर-सरकारी संस्थान, विशेष रूप से वे जो छोटे और गैर-अभिजात वर्ग के हैं, अपने वित्त-पोषण के लिए शुल्क पर बहुत अधिक निर्भर हैं। लेकिन सरकारें अधिकांश देशों में गैर-सरकारी संस्थानों को वित्तपोषित करने में भी मदद करती हैं। कुछ अकादमिक कर्मचारियों को इंडोनेशिया में सिविल सेवकों के रूप में सब्सिडी दी जाती है, और थाईलैंड में गैर-सरकारी संस्थानों के लिए एक विशेष निधि उपलब्ध है। सार्वजनिक धन उपलब्ध होने से अनुसंधान पहलों को प्रोत्साहित करने में या यदि यह सशर्त हो, तो संस्थानों को गुणवत्ता या समानता मानकों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करके गैर-सरकारी प्रावधान में सुधार करने में मदद कर सकती है।

परिवारों ने उच्च स्तरीय शिक्षा वित्त-पोषण के लिए एक बड़ा हिस्सा रखा है, जिससे सरकारी और गैर-सरकारी समर्थन दोनों की आवश्यकता बढ़ रही है। सरकारें गैर-सरकारी संस्थानों को लक्षित शुल्क सब्सिडी की पेशकश कर सकती हैं, जैसे कि ब्राजील और चिली में, या सभी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए 70 से अधिक देशों में उपलब्ध छात्र ऋण कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी दे सकती हैं। गैर-सरकारी कार्यकर्ता कंपनियों, फाउंडेशनों, गैर-सरकारी संगठनों और परोपकारियों द्वारा भुगतान की गई छात्रवृत्ति के साथ-साथ छात्र ऋण या आय-साझा समझौते प्रदान करके परिवारों की लागत को कवर करने में मदद करते हैं।

गैर-सरकारी कार्यकर्ता फीस से परे वित्त संस्थानों की मदद करते हैं। सामान्य प्रणाली में बाजार की गतिविधियों में शामिल होना जैसे भूमि पट्टे का प्रस्ताव करना, उत्पादों और सेवाओं का व्यावसायीकरण, तथा ऋण और बांड के माध्यम से पूंजी जुटाना शामिल है। 2020 के मध्य तक, दुनिया भर के विश्वविद्यालयों द्वारा बांड जारी करना 11.4

बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था, जो 2019 की दोगुने से अधिक राशि है। दानदाता और परोपकारी भी संस्थानों के लिए राजस्व के महत्वपूर्ण गैर-शुल्क स्रोत जुटाते हैं, जो 2020 में अमेरिका में उच्च स्तरीय संस्थानों द्वारा जुटाए गए कुल राजस्व के आधे से अधिक है।

गैर-सरकारी कार्यकर्ता विभिन्न चैनलों के माध्यम से उच्च स्तरीय शिक्षा को प्रभावित करते हैं। कुछ प्रणालियां, जैसे अनुसंधान भागीदारी, पैरवी करना, व्यवसायिक शासन सुधार और वकालत, पारदर्शिता बढ़ाने और क्षेत्र को सुदृढ़ करने में मदद कर सकते हैं। अन्य, जैसे कि लाभ अर्जित करने वाले संस्थानों द्वारा राजनेताओं (जैसे ब्राजील और अमेरिका में) को बड़ी संख्या में दान देना, नीति निर्धारण पर अनुचित प्रभाव डाल सकता है और संस्थागत स्वायत्तता को कमजोर कर सकता है।.

तकनीकी, व्यावसायिक और प्रौढ़ शिक्षा

गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रावधान के विस्तार में मदद की है। दुनिया भर में, 2019 में माध्यमिक, गैर-उच्च स्तरीय शिक्षा में 38.5% छात्रों ने निजी संस्थानों को चुना। ओईसीडी देशों में, अल्पावधि उच्च स्तरीय व्यावसायिक कार्यक्रमों में 44% छात्र निजी संस्थानों में नामांकित थे। गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं के साथ सहयोग का उद्देश्य तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीवीईटी) प्रणालियों को श्रम बाजार की मांगों के अनुसार बनाना और समेकित सार्वजनिक टीवीईटी प्रणाली लागू करने वाले देशों में भी उनकी क्षमता और संसाधनों को बढ़ावा देना है। अन्य संदर्भों में, गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक खरीद, स्वायत्त प्रशिक्षण पहल और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा के प्रावधान को पूरा किया है, जिसका समन्वय अधिकतर राज्य द्वारा किया जाता है। गरीब देशों में, गैर-सरकारी कार्यकर्ता वंचित समूहों को समान रूप से टीवीईटी तक पहुंच प्रदान करते हैं।

नियोक्ता औपचारिक और अनौपचारिक प्रशिक्षुता को महत्व देते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्कूल-टू-वर्क ट्रांजिशन सर्वे में पाया गया कि 33 देशों में 15 से 35 वर्ष के प्रतिभागियों में से 5 में से 1 से कम ने अपनी शिक्षा के भाग के रूप में कम से कम एक प्रशिक्षुता हासिल की। कम आय वाले देशों में कम भागीदारी को श्रम बाजारों और प्रशिक्षण प्रणालियों की अनौपचारिकता से जोड़ा जा सकता है। यदि ये पर्याप्त रूप से नियंत्रित और मान्यता-प्राप्त नहीं है, तो प्रशिक्षुता से जुड़े प्रोत्साहनों को समाप्त किया जा सकता है। मध्यस्थ संगठन नियोक्ताओं के साथ संवाद की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, सीखने में सुधार कर सकते हैं और सही उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं, खासकर उन देशों में जहां कोई ठोस प्रशिक्षुता प्रदान नहीं की जाती है।

सतत कौशल विकास अधिकतर निजी नियोक्ताओं द्वारा प्रदान किया जाता है। जबकि औपचारिक टीवीईटी मुख्य रूप से उन व्यवसायों को दी जाती है जो पारंपरिक शिक्षा तक सीमित रहते हैं और जिन पर स्वचालित होने, पुन: कौशल प्राप्त करने और उन्नत कौशल का जोखिम बना रहता है। अनौपचारिक और नियोक्ता द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण दिए जाते हैं; जो भी प्रस्ताव दिया जाता है वह सीधे तौर पर कंपनी के आकार पर निर्भर करता है। विश्व बैंक के स्टेप कौशल माप कार्यक्रम के परिणाम बताते हैं कि नियोक्ता औपचारिक सार्वजनिक या निजी प्रदाताओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले बाहरी कार्यक्रमों के लिए कार्य के दौरान प्रशिक्षण को पसंद करते हैं।

कौशल विकास प्रणालियों में सहभागी व्यवस्था चुनौतीपूर्ण है। टीवीईटी प्रणालियां मुख्य रूप से केंद्रीकृत होती हैं। 150 से अधिक देशों में राष्ट्रीय योग्यता ढांचे का उद्देश्य टीवीईटी व्यवस्था को अधिक भागीदारीपूर्ण और उद्देश्य के लिए उपयुक्त बनाना है, हालांकि कौशल की पारदर्शिता और प्रासंगिकता में सुधार सार्वजनिक प्राधिकारियों के लिए प्राथमिकता बनी हुई है। टीवीईटी प्रणाली की प्रभावशीलता आंशिक रूप से लागू गुणवत्ता आश्वासन तंत्र द्वारा बाधित होती है। निजी और शिक्षा क्षेत्रों के बीच वार्ता, पाठ्यक्रम के विकास के बजाय कौशल पहचान पर केंद्रित रहती है। आर्थिक परिवर्तन का भली-भांति सामना करने वाली कौशल प्रणालियाँ वे हैं जो त्रिपक्षीय दृष्टिकोणों पर निर्भर रहती हैं, अर्थात् जो सामाजिक और आर्थिक कार्यकर्ताओं को शामिल करती हैं। श्रम बाजार की जरूरतों के हिसाब से सुधार के लिए क्षेत्र कौशल परिषदों के माध्यम से ज्ञान-उन्मुख सार्वजनिक-निजी भागीदारी स्थापित की गई है।

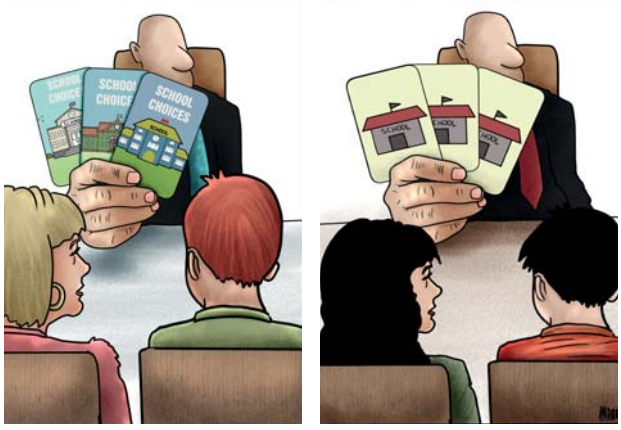
कौशल विकास प्रणाली सरकारी और गैर-सरकारी वित्त-पोषण पर निर्भर करती है। प्रत्यक्ष सरकारी आवंटन के अलावा, टीवीईटी प्रणाली निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क या वित्त-पोषण कंपनियों के माध्यम से वित्त-पोषण में विविधता लाने का प्रयास करती है। गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं को भी मिश्रित परिणाम के साथ प्रतिस्पर्धी खरीद के माध्यम से सीधे तौर पर शामिल किया गया है। नियोक्ताओं को शुल्क-अनुदान कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। फिर भी, कंपनियां प्रशिक्षण में कम निवेश करती हैं, क्योंकि इसके लिए प्रोत्साहन सीधे श्रम बाजार से आवश्यक कौशल प्राप्त करने के प्रोत्साहन से कम होता है। सरकारें व्यक्तिगत शिक्षण खातों या पात्रताओं के माध्यम से प्रशिक्षण की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लागत को कवर करके व्यक्तियों को प्रोत्साहन प्रदान करती हैं।

गैर-सरकारी और सामुदायिक संगठन व्यापक रूप से प्रौढ़ कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। सामुदायिक शिक्षा केंद्रों, साक्षरता कार्यक्रमों आदि के माध्यम से, गैर-सरकारी संगठन और नागरिक समाज संगठन उन कमजोर प्रौढ़ वयस्क समूहों से संपर्क करते हैं, जो पारंपरिक रूप से औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए थे। कुछ मामलों में, सरकारें राष्ट्रीय प्रौढ़ साक्षरता और द्वितीय अवसर कार्यक्रमों जैसी उनकी सेवाओं पर भरोसा करती हैं; अन्य संदर्भों में, ऐसे समूहों ने सरकार के प्रौढ़ शिक्षा प्रावधान को चुनौती दी है, विशेष रूप से लैटिन अमेरिका में, उदाहरण के लिए प्रौढ़ साक्षरता में गैर-प्रमुख भाषाओं को बढ़ावा देना; अन्य संदर्भों में, वे दाता की प्राथमिकताओं से प्रभावित होते हैं। सरकारी नीतियों के विकास में उनका जुड़ाव सीमित रहता है, हालांकि पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में, शक्तियों के निष्पक्ष विकेंद्रीकरण और आउटसोर्सिंग रणनीति के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जिसमें सरकार

पर्यवेक्षण और संसाधनों का वितरण कर रही है, जबकि गैर-सरकारी कार्यकर्ता प्रावधान के प्रभारी हैं।

निजी क्षेत्र ने प्रौढ़ शिक्षा, विशेषकर भाषा सीखने में अपनी भूमिका का विस्तार किया है। निजी कंपनियां सामुदायिक विकास के माध्यम से वयस्क शिक्षा में शामिल हो सकती हैं, जो प्राय: कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रावधान के भाग के रूप में होता है। भाषा सीखने और मूल्यांकन की बढ़ती आवश्यकता ने लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों को आकर्षित किया है। अर्जेंटीना और पेरू में लगभग 40% अंग्रेजी सीखने वाले निजी भाषा संस्थानों के साथ अध्ययन करते हैं। मोबाइल-समर्थित भाषा सीखना भी फैल रहा है, लेकिन यह कितना प्रभावी है, यह बहस का विषय है।

सिफारिशें



सामान्य तौर पर सरकारी बनाम निजी विरोधाभास से परे, विभिन्न प्रकार के गैर-सरकारी स्कूल भी हैं। इसके अलावा, गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं की भूमिका स्कूली शिक्षा के प्रावधान से परे विभिन्न शिक्षा स्तरों पर और कई प्रभावी चैनलों के माध्यम से कई अन्य कार्यकलापों तक फैली हुई है। नीति निर्माताओं के लिए सवाल यह नहीं है कि शिक्षा में गैर-सरकारी भागीदारी गुणवत्ता के सहमत मानकों को पूरा करती है या नहीं, बल्कि यह भी है कि गैर-सरकारी कार्यकर्ता शिक्षा में समानता और सभी को शामिल करना सुनिश्चित करने के प्रयासों में कैसे मदद करते हैं या बाधा डालते हैं।

शिक्षा के अधिकार की रक्षा करने और उसे पूरा करने के सरकारों के कार्य के संबंध में वित्त-पोषण और प्रावधान से संबंधित दो कार्यनीतिक दिशाएँ विशिष्ट हैं। पहला, सरकारों ने 2015 में प्रतिज्ञा की थी कि सभी बच्चों और युवाओं को सार्वजनिक रूप से वित्त-पोषित क्रमश: एक वर्ष तक प्री-प्राइमरी और 12 वर्ष तक प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षा मुफ्त प्रदान की जाएगी। हालांकि, तीन में से एक देश सकल घरेलू उत्पाद का 4% से कम और कुल सार्वजनिक खर्च का 15% शिक्षा के लिए समर्पित करते हैं, कई देश अपेक्षित निधियों के साथ इस प्रतिबद्धता को पूरा नहीं करते हैं। दूसरा, सरकारों को यह तय करने की जरूरत है कि वे शिक्षा प्रदान करने और उसका प्रबंधन करने में कितनी ठोस भूमिका निभाएंगे। स्कूल की पसंद और गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं के संबंध में उनके दृष्टिकोण व्यापक रूप से भिन्न हैं।

विभिन्न गैर-सरकारी कार्यकर्ता शिक्षा के कई पहलुओं में अधिक भूमिका निभा रहे हैं। व्यवसाय इस बात को ध्यान में रखते हैं कि क्या शिक्षा एक आकर्षक गतिविधि है तथा अपने सामान और सेवाओं का विपणन कैसे करें, लेकिन यह भी कि वे किसके प्रति जवाबदेह हैं: केवल शेयरधारक या अन्य लोगों के प्रति भी? गैर-सरकारी संगठन और नागरिक समाज संगठन क्या जरूरी है उसे चुनते हैं और तय करते हैं कि उनसे कैसे निपटा जाए: क्या उन्हें कमियों को दूर करना चाहिए या सरकार को ऐसा करने के लिए कहना चाहिए? फ़ाउंडेशन प्राथमिकताएं भी निर्धारित करते हैं और यह देखते हैं कि समाज को कैसे प्रभावित किया जाए तथा शिक्षा प्रणालियों पर कितनी गहराई से काम किया जाए। शिक्षक और उनके संगठन ऐसे विकल्प का पता लगाते हैं जो सार्वजनिक शिक्षा प्रणालियों में विश्वास को मजबूत करते हैं या मिटा सकते हैं।

रिपोर्ट में की गई अपील - कौन चुनता है? कौन वंचित रह जाता है? – वस्तुत: नीति निर्माताओं के लिए मौलिक विकल्पों: समानता और पसंद की स्वतंत्रता के बीच; पहल को प्रोत्साहित करने (अर्थात् प्रणाली में कहीं भी गुणवत्ता में सुधार) तथा मानकों को स्थापित करने (अर्थात् सभी शिक्षार्थियों के लिए गुणवत्ता में सुधार) के बीच; विभिन्न साधनों और जरूरतों के जनसंख्या समूहों के बीच; उनकी तात्कालिक प्रतिबद्धताओं (अर्थात् एसडीजी 4 के तहत 12 साल तक मुफ्त शिक्षा) और उन प्रतिबद्धताओं के बीच जिन्हें उत्तरोत्तर साकार किया जाना है (उदाहरण के लिए माध्यमिक शिक्षा के बाद); और शिक्षा और अन्य सामाजिक क्षेत्रों के बीच गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं के साथ संबंधों के प्रश्न पर विचार करने का एक निमंत्रण है।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए, #राइट द रूल्स की मदद करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें तैयार की गईं ताकि शिक्षा में वित्त-पोषण, गुणवत्ता, शासन, नवाचार और नीति निर्माण में समानता सुनिश्चित की जा सके। इसका उद्देश्य समानता से समझौता किए बिना बेहतरीन शिक्षा देने के लिए गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं के योगदान का दोहन करना है। इस क्षमता को जुटाने से सरकारों को सरकारी प्रावधान में निम्न गुणवत्ता और असमानता का उद्देश्यपूर्ण ढंग से समाधान करने का अवसर मिल सकता है। सिफारिशें मुख्य रूप से सरकारों के लिए की गई हैं, जिन्हें समानता और सभी को शामिल करने के आधार पर पांच मुख्य प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर देने हैं। हालांकि, इनका इस्तेमाल एसडीजी 4 में हुई प्रगति का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध सभी शिक्षा कार्यकर्ताओं द्वारा सलाह देने वाले एक टूल के रूप में भी किया जा सकता है। इस प्रकार, सिफारिशें सभी कार्यकर्ताओं, सरकारी और गैर-सरकारी को समान रूप से #राइट बाई द रूल्स का पालन करने की अपील करती हैं।

1. क्या शिक्षा का वित्तपोषण कुछ शिक्षार्थियों के पक्ष में है और दूसरों को इससे वंचित करता है?

प्री-प्राइमरी के 1 वर्ष तथा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के 12 वर्षों को निःशुल्क बनाने की प्रतिबद्धता को पूरा करें - लेकिन यदि समानता सुनिश्चित की जा सकती है तो सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित होने का अर्थ सार्वजनिक रूप से प्रदान करना नहीं है।



सरकारों को निवास स्थानों के पास बेहतरीन शिक्षा मुफ्त प्रदान करनी चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परिवार को शिक्षा की सामग्री और सेवाओं के लिए भुगतान न करना पड़े जिसके लिए उनके देशों ने मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता की है।

सरकारों को परिवार की आय और व्यय सर्वेक्षणों का उपयोग करते हुए, लोगों द्वारा शिक्षा पर अपनी जेब से खर्च की निगरानी करनी चाहिए। वे प्राय: मुआवजे की कम लागत पर ध्यान नहीं देते हैं जो असमानता को बढ़ाती हैं।

सभी प्रदाताओं, चाहे सरकारी हों या गैर-सरकारी, को छात्रों को एक-समान शर्तें प्रदान करनी चाहिए। शिक्षा को सार्वजनिक रूप से वित्त-पोषित करने की प्रतिबद्धता का अर्थ यह नहीं है कि सभी शिक्षा सरकारी रूप से प्रदान की जानी चाहिए। लेकिन सभी शिक्षा संस्थानों को सामान्य नियमों, वित्तीय सहायता और निगरानी तंत्र सहित एक प्रणाली के भाग के रूप में माना जाना चाहिए।

प्रावधान में विविधता लाने के किसी भी प्रयास को इस तरह से बनाया जाना चाहिए जिससे समानता सुनिश्चित हो। पब्लिक स्कूल प्रबंधन का ठेका देने, निजी स्कूलों को परिचालन लागत के लिए सब्सिडी देने या परिवारों को उनकी पसंद के स्कूल में दाखिला लेने के लिए धन उपलब्ध कराने से केवल अमीर छात्रों को ही फायदा होना समाप्त हो सकता है।

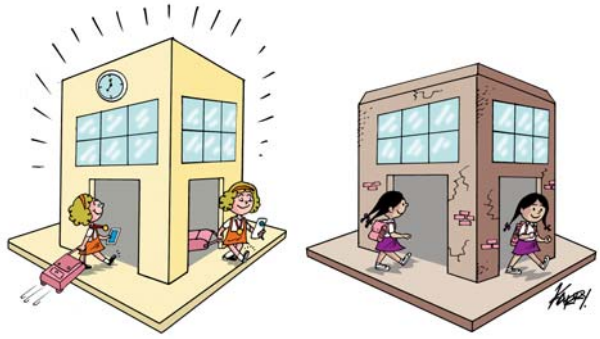
स्कूलों को छात्रों का चयन नहीं करना चाहिए। देश शिक्षा में भेदभाव को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, यह एक ऐसा सिद्धांत है जो स्कूल की दाखिला नीति में परिलक्षित होना चाहिए। इसके अलावा, परिवारों और छात्रों को स्कूल चुनने का अधिकार देने से असमानता पैदा नहीं होनी चाहिए।

सरकार द्वारा वित्त-पोषित गैर-सरकारी प्रदाताओं द्वारा कोई फीस नहीं लेनी चाहिए। जबकि सभी देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्री-प्राइमरी, प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा मुफ्त हो, कई इस आदर्श का पालन नहीं करते हैं। यहां तक कि सरकार पर निर्भर निजी संस्थान भी फीस लेते हैं।

मुनाफ़ा कमाना मुफ्त प्री-प्राइमरी, प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा की गारंटी देने की प्रतिबद्धता के खिलाफ है। लाभ कमाने को नियंत्रित या प्रतिबंधित करने का उपयोग स्कूल की पसंद की नीतियों का समाधान करने के लिए किया जा सकता है जो असमानता को बढ़ाती हैं।

2. क्या सभी शिक्षार्थियों को बेहतरीन शिक्षा प्राप्त होती है जिसके वे हकदार हैं, या इससे वंचित रहते हैं?

ई-गुणवत्ता मानक स्थापित करें जो सभी सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षा संस्थानों पर लागू हों।



सरकारों को सभी शिक्षा संस्थानों पर लागू होने वाले गुणवत्ता मानकों को स्थापित करना चाहिए। गुणवत्ता मानकों से केवल इनपुट ही नहीं बल्कि परिणाम भी हासिल होने चाहिए, उन लोगों की रक्षा करें जिन्हें इसे खोने का सबसे अधिक खतरा है। उन्हें सुरक्षा और सभी को शामिल करने को भी कवर करना चाहिए। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल कहां हैं और उन्हें सुधारने में मदद करनी चाहिए। प्रत्येक स्कूल, चाहे सरकारी हो या गैर-सरकारी, को अपनी उपलब्धि का मूल्यांकन करना चाहिए और सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

सभी स्कूलों में शिक्षकों को पेशेवर के रूप में महत्व दिया जाना चाहिए। शिक्षक योग्यता और व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदाता द्वारा भिन्न नहीं होने चाहिए। शिक्षक श्रम बाजार का बंटा होना और शिक्षक के वेतन और शर्तों में व्यापक असमानता दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के प्रबल

संकेत हैं। सरकारों को इस तरह के असंतुलन के सभी मूल कारणों को धीरे-धीरे दूर करना चाहिए।

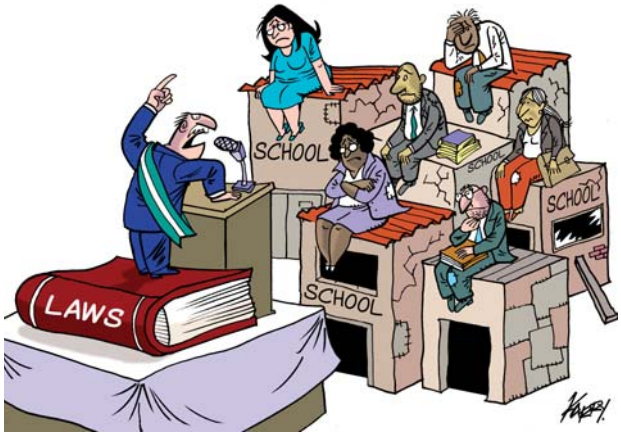
मानकों की निगरानी करने और उन्हें लागू करने के लिए गुणवत्ता आश्वासन तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। स्कूल निरीक्षण, मूल्यांकन और सीखने का आकलन करने के माध्यम से सरकारी देखरेख प्रदाता की परवाह किए बिना आम बात होनी चाहिए। इन तंत्रों को सरकारी कार्यान्वयन क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए।

देशों को तकनीकी, व्यावसायिक और उच्च स्तरीय शिक्षा में ठोस गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं को लागू करना चाहिए। चूंकि सरकारें प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तियों को सब्सिडी देती हैं या कंपनियों के साथ अनुबंध करती हैं, इसलिए उन्हें सबसे अधिक वंचितों की रक्षा करने करनी चाहिए, जिनके साथ धोखा होने की संभावना रहती हैं। गुणवत्ता स्पेक्ट्रम के सबसे निचले पायदान पर शिक्षा प्रदान करने और कदाचार में लिप्त होने के कारण लाभ कमाने वाले विश्वविद्यालय जांच के दायरे में आ गए हैं।

सरकारों को निजी पूरक ट्यूशन को रोकना चाहिए जो प्रणाली की गुणवत्ता और समानता पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। बेहतर देखरेख के लिए ट्यूटर टीचिंग परमिट आवश्यकताओं से लेकर ऑनलाइन रजिस्टरों तक नीतिगत प्रतिक्रियाएं भिन्न-भिन्न होती हैं। प्रतिबंध भी एक विकल्प है, लेकिन इससे अनौपचारिक बाजार बन सकते हैं। प्राथमिकता मूल कारणों से निपटने पर होनी चाहिए, जैसे शिक्षक का कम वेतन और उच्च-जोखिम वाली अंतिम परीक्षा।

3. क्या विनियम प्रभावी और व्यवहार्य हैं या क्या उनके अनचाहे परिणाम मिले हैं जो वंचित शिक्षार्थियों के पक्ष में नहीं हैं?

सभी सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षा संस्थानों पर लागू होने वाली सामान्य निगरानी और समर्थन प्रक्रियाओं की स्थापना करें।



सरकारों को एक स्पष्ट दृष्टिकोण और ढांचा बनाना चाहिए कि वे कैसे गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं को शामिल करना चाहते हैं और नियमों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को बताना चाहते हैं। विनियमों को प्रशासनिक विवरण और काल्पनिक इनपुट मानकों पर नहीं बल्कि शिक्षा प्रक्रियाओं और परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों से मांगी गई जानकारी के साथ समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए तथा उनका समायोजन पारदर्शी और सहभागी तरीके से किया जाना चाहिए।

शिक्षा प्राधिकारियों द्वारा शिक्षा प्रदाताओं को हमेशा शिक्षा संस्थाओं के रूप में नियंत्रित किया जाना चाहिए न कि बाजार विनियामकों द्वारा केवल वाणिज्यिक संस्थाओं के रूप में। कुछ प्रदाताओं को बाल देखभाल और शिक्षा, निजी पूरक ट्यूशन और व्यावसायिक प्रशिक्षण में व्यवसायों के रूप में नियंत्रित किया जाता है। इसी तरह, अन्य प्रदाताओं की निगरानी सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय या धार्मिक प्राधिकारियों द्वारा की जाती है।

विनियम सरल, पारदर्शी और कारगर होने चाहिए। विरोधाभास यह है कि जहां नियमों की आवश्यकता होती है वहां विनियामक क्षमता सबसे कम होती है, और भ्रष्टाचार की संभावना सबसे अधिक रहती है। जहां अव्यावहारिक नियमों की निगरानी और उन्हें लागू करने की क्षमता का अभाव है, वहां विनियम अप्रासंगिक और निरर्थक हो जाते हैं।

सरकारें जिन चीजों को नियंत्रित करना चाहती हैं उनके बारे में उन्हें निष्ठावान होना चाहिए। निगरानी और समर्थन प्रक्रिया सामान्य होनी चाहिए, जिससे यह परिलक्षित हो कि सरकारें सभी बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखती हैं, चाहे वे किसी भी प्रकार के स्कूल में जाते हों। सरकारों को भी गैर-सरकारी प्रदाताओं के साथ विश्वास का संबंध बनाने की जरूरत है, जिससे उन्हें अपने स्कूलों को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए सही प्रोत्साहन मिल सके।

4. क्या शिक्षा के लिए अच्छे विचारों को प्रोत्साहित किया जाता है या दबा दिया जाता है?

सार्वजनिक हित में शिक्षा प्रणाली के माध्यम से आधुनिकता का व्यापक प्रसार किया जाना चाहिए।



नीति निर्माताओं को आधुनिकता की पहचान करने और अच्छे विचारों को विकसित करने के लिए समय और प्रदान करनी चाहिए। अच्छे विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। शिक्षा एक सामाजिक प्रयास और एक जटिल प्रणाली है। नीति निर्माताओं के लिए चुनौती नवीनता को बढ़ावा देना है, विशेषकर जब आम जनता द्वारा प्रयोग की तुलना में अनुपालन को प्राथमिकता देने की संभावना हो।

सरकार को एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करना चाहिए जो सभी के लिए हो, और आवश्यकता अनुसार दृष्टिकोण को प्राथमिकता देती हो। नवीनता को बढ़ावा देने के लिए विश्वास रखने की संस्कृति बनाने की जरूरत है। विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ताओं को बातचीत और सहयोग करने के लिए माहौल पैदा करने तथा उन्हें मंच प्रदान करने से विभिन्न विचारों और विशेषज्ञता के स्रोतों का लाभ उठाते हुए सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को प्रासंगिक बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

आरंभ में, सरकारों को सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में नवीनता को बढ़ावा देना चाहिए। उन्हें यह संदेश देना होगा कि वे उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्हें शिक्षा और उनके निर्धारकों की निगरानी करनी चाहिए, यह देखना चाहिए कि अच्छी प्रथाएं कहां पनप रही हैं, कार्यकर्ताओं को अनुभवों को साझा करने, अच्छे विचारों को लागू करने तथा उनका विस्तार करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए।

सरकारों को गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं से भी सबक लेना चाहिए। हाशिए पर रहने वाले शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए स्वायत्त, प्रासंगिक और लचीला दृष्टिकोण नई समझ पैदा कर सकता है, जिससे सरकारों को लाभ होना चाहिए, इस बात को देखते हुए कि कम क्षमता उन्हें सरकारी स्कूलों की उचित निगरानी और मूल्यांकन करने से रोकती है, गैर-सरकारी स्कूलों की तो बात ही छोड़ दें।

सरकार की भूमिका नई खोज करने के लिए सही माहौल तैयार करना है। शिक्षा को ऐसे बाजार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए जहां शिक्षा 'देने वाले' अन्य प्रदाताओं से आगे निकल जाते हैं। इसके बजाय, नए विचारों को साझा करने, परीक्षण करने और, यदि सिद्ध हो, अपनाया जाना चाहिए, जिससे सरकार उन्हें शिक्षा प्रणाली के माध्यम से फैलाने में मदद करे और गैर-सरकारी कार्यकर्ता उन्हें आर्थिक उद्देश्यों के बजाय जनहित में स्वेच्छा से लागू करें।

5. क्या शिक्षा में सार्वजनिक बहस के लिए सभी को बोलने का समान अवसर दिया जाता है?

निहित स्वार्थों को रोकने के लिए सार्वजनिक शिक्षा नीति प्रक्रिया की पारदर्शिता और अखंडता बनाए रखना।



नीति निर्माताओं को सभी हितधारकों के विचारों और दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होगा। लेकिन जिस तरह नीति निर्माताओं को सभी विचारों को स्वागत करना चाहिए, उसी तरह यह भी आवश्यक है कि शिक्षा कानून, नीति और विनियम के बारे में सार्वजनिक अधिकारियों के साथ संवाद पारदर्शी हो। कुछ कार्यकर्ता जनता की भलाई के बजाय अपनी बाजार हिस्सेदारी या राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए काम करते हैं।

सरकारों को निहित स्वार्थों द्वारा लॉबिंग के खिलाफ निगरानी और सुरक्षा करनी चाहिए ताकि सार्वजनिक नीति को गलत तरीके से प्रभावित करने से रोका जा सके। सार्वजनिक नीति प्रक्रियाओं में विश्वास बनाए रखने के लिए, क्षमता के आधार पर पारदर्शिता को बढ़ावा देने के कई उपाय लागू किए जा सकते हैं, जिसमें राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दान का खुलासा करने को बढ़ावा देने वाले अधिनियम तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठकें, और महत्वपूर्ण पदों को छोड़ने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ नियम बनना शामिल हैं जिनसे वे निजी लाभ प्राप्त कर सकते हैं तथा पैरवी करने वालों और उनके प्रायोजकों के खिलाफ सार्वजनिक पद ग्रहण कर सकते हैं। ये सिफारिशें अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर भी लागू होती हैं, जिसके लिए गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने की स्पष्ट नीति बनाए जाने की आवश्यकता है जो समानता और सभी को शामिल करने को प्राथमिकता देते हैं।

सतत विकास लक्ष्यों में शिक्षा की निगरानी

सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को प्राप्त करने का आधा सफर तय करने के पास पहुंचते हुए, निगरानी ढांचे के विकास और देशों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हालाँकि, कोविड-19 महामारी ने दोनों मामलों में बड़ी बाधा पहुंचाई है। इससे न केवल शिक्षा में प्रगति की निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक टूल प्रभावित हुए हैं, बल्कि लक्ष्यों पर भी पुनर्विचार करना पड़ सकता है।

देशों ने राष्ट्रीय एसडीजी 4 बेंचमार्क प्रस्तुत किए हैं

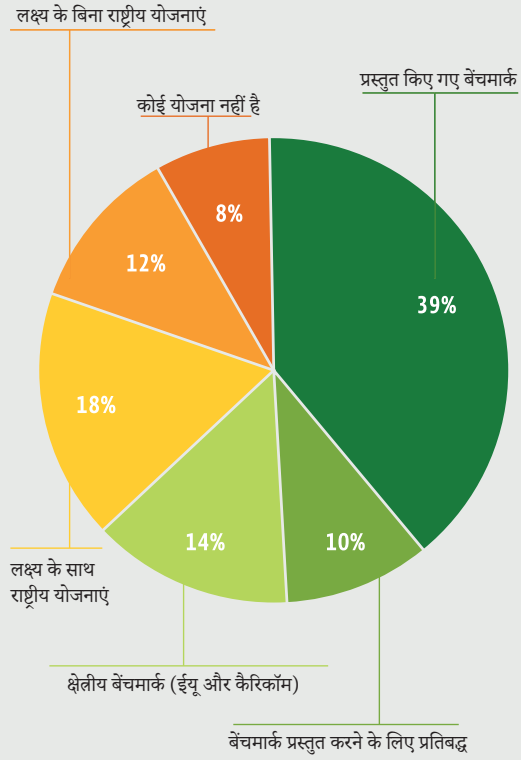
शिक्षा कार्य ढांचा 2030 ने देशों से एसडीजी 4 संकेतकों के लिए 'उपयुक्त मध्यवर्ती बेंचमार्क (जैसे 2020 और 2025 के लिए)' स्थापित करने का आह्वान किया, ताकि प्रत्येक देश को उनकी प्रारंभिक स्थितियों को देखते हुए वैश्विक एजेंडा में योगदान देने के लिए तैयार किया जा सके। यूनेस्को सांख्यिकी संस्थान (यूआईएस) और जीईएम रिपोर्ट टीमों ने इस दिशा में अंतरराष्ट्रीय समुदाय को जुटाने के लिए काम किया है। 2019 में बेंचमार्किंग के लिए सात एसडीजी 4 संकेतकों के चयन और अक्तूबर 2020 में वैश्विक शिक्षा बैठक घोषणा की सिफारिश के बाद 'प्रगति में तेजी लाने और प्रमुख एसडीजी 4 संकेतकों के प्रासंगिक और यथार्थवादी बेंचमार्क का प्रस्ताव' करने के लिए, देशों को 2025 और 2030 के लिए अक्तूबर 2021 तक राष्ट्रीय बेंचमार्क मूल्य प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। 39% देशों द्वारा मूल्य प्रस्तुत किए गए थे। अन्य 10% ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जबकि अतिरिक्त 14% यूरोपीय संघ और कैरेबियन समुदाय के सदस्य हैं, जिन्होंने क्षेत्रीय बेंचमार्क प्राप्त किए हैं **(चित्र 3)**।

2025 और 2030 के लिए आधारभूत मूल्यों और प्रस्तुत राष्ट्रीय बेंचमार्क मूल्यों की जानकारी अब ग्लोबल एजुकेशन ऑब्जर्वेटरी में शामिल की गई है, जो शिक्षा से संबंधित डेटा का एक नया प्रवेश द्वार है। यूआईएस और जीईएम रिपोर्ट 2022 के प्रारंभ में इस प्रक्रिया के परिणामों का विश्लेषण करते हुए एक बेसलाइन रिपोर्ट जारी करेगी। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला जाएगा कि देश, क्षेत्र और दुनिया का लक्ष्य कहां है। उन देशों को शिक्षा लक्ष्य विकसित करने में मदद करने के लिए एक प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की जाएगी जहां ये अभी भी गायब हैं, लेकिन साथ ही, जहां प्रासंगिक हैं, ताकि डेटा के प्राप्त होने पर राष्ट्रीय बेंचमार्क में कोविड-19 के संभावित प्रभाव को दर्शाया जा सके।

चित्र 3:

तीन में से दो देशों ने एसडीजी 4 बेंचमार्क-निर्धारण प्रक्रिया में भाग लिया है

अक्तूबर 2021 तक राष्ट्रीय एसडीजी 4 बेंचमार्क प्रस्तुत करने की स्थिति के अनुसार देशों का अनुपात



जीईएम सांख्यिकी लिंक: https://bit.ly/GEM2021_Summary_fig3

स्रोत: यूआईएस और जीईएम रिपोर्ट टीम।

ईयू = यूरोपीय संघ; कैरिकोम = कैरिबियन समुदाय

कोविड-19

कोविड-19 ने एसडीजी 4 प्राप्त करने की संभावनाओं और प्रगति की निगरानी के साधनों को प्रभावित किया है

कोविड-19 दुनिया की सभी शिक्षा प्रणालियों को एक साथ प्रभावित करने वाला अब तक का सबसे गंभीर संकट है। मार्च 2020 और अक्तूबर 2021 के बीच 28% दिनों के लिए स्कूल बंद थे और 26% दिनों के लिए आंशिक रूप से बंद थे। अप्रैल 2020 (95%) में कोविड चरम पर पहुंच गया था। सितंबर 2020 और अगस्त 2021 के बीच, स्कूल आधे दिनों के लिए बंद या आंशिक रूप से बंद रहे (**चित्र 4**)। कई देशों ने अपने स्कूलों को आंशिक रूप से खुले के रूप में वर्गीकृत किया, तब भी जब अधिकांश बंद थे।

आधिकारिक एसडीजी 4 आंकड़े, अधिकतर मामलों में, 2019 के लिए हैं और महामारी से पहले की स्थिति को दर्शाते हैं। जून और सितंबर 2020 के बीच 129 शिक्षा मंत्रालय की योजना इकाइयों के यूआईएस मूल्यांकन में पाया गया कि दो-तिहाई को डेटा संग्रह में देरी करनी पड़ी या इसे अगले स्कूल वर्ष के लिए स्थगित करना पड़ा क्योंकि उन्होंने रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करने की उनकी क्षमता पर मध्यम या गंभीर प्रभाव का अनुभव किया। महामारी के दौरान सर्वेक्षण का कार्य भी बुरी तरह प्रभावित हुआ था। कुछ बड़े घरेलू सर्वेक्षण कार्यक्रम फोन सर्वेक्षण में बदल गए। लेकिन 2020 में योजनाबद्ध या पहले से चल रहे 25 से अधिक सर्वेक्षणों को क्षेत्रीय कार्य में देरी का सामना करना पड़ा। परिणाम सावधानी पूर्वक बनाने होंगे कि वास्तव में क्षेत्रीय कार्य कब किया गया था और क्या उस समय आस-पास के स्कूल खुले थे। इसके अलावा, शिक्षण मूल्यांकन प्रभावित हुए थे। उदाहरण के लिए, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट के 2021 दौर को एक साल के लिए टाल दिया गया था।

तरीकों, नमूनों, समय और संदर्भों में अंतर के साथ-साथ अत्यधिक स्रोतों का अर्थ है कि कोविड-19 के प्रभाव के कारण जानकारी जुटाने का कार्य चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। प्रशासनिक आंकड़ों के अभाव में, इथियोपिया, घाना और सेनेगल में सर्वेक्षण प्रारंभिक साक्ष्य प्रदान करते हैं कि फिर से स्कूल खुलने पर बच्चे स्कूल आ रहे हैं, हालांकि पुनरावृत्ति दर में वृद्धि का अर्थ यह हो सकता है कि ड्रॉपआउट केवल स्थगित हुआ है।

दो मुख्य चिंताएं हैं शिक्षा में आए व्यवधान का प्रभाव, तनाव के कारण पढ़ाई में बाधा तथा अधिक वंचित शिक्षार्थियों पर अन्य प्रभाव। विश्व स्तर पर तीन बच्चों में से केवल एक और सबसे गरीब बच्चों में से छह में से एक के पास इंटरनेट की पहुंच थी। इस प्रकार सबसे प्रभावी उपलब्ध दूरस्थ शिक्षा साधनों से बड़ी संख्या में शिक्षार्थी वंचित रह गए थे, और इस तरह के साधनों का विस्तार करने के प्रयास अल्पावधि से मध्यम अवधि तक समानता लाने के प्रतिकूल होंगे। मोबाइल लर्निंग ऐप्स का उपयोग, जिस पर मीडिया का बहुत ध्यान गया, छह उप-सहारा अफ्रीकी देशों के एक सर्वेक्षण में सबसे कम सामान्य दूरस्थ शिक्षा दृष्टिकोण था, जिसका उपयोग नाइजीरिया में 17% से अधिक बच्चों और इथियोपिया में 12% द्वारा नहीं किया गया था तथा बुर्किना फासो, मलावी, माली और युगांडा में शायद ही किसी बच्चे द्वारा किया गया था।

शिक्षा पर प्रभाव स्कूल बंद होने की अवधि, दूरस्थ शिक्षा के तरीकों और छात्रों को दिए जाने वाले समर्थन की सीमा पर निर्भर करेगा, जो सभी देशों के बीच और उनके भीतर बहुत भिन्न-भिन्न है। अधिकांश अध्ययन उच्च आय वाले देशों में किए गए हैं। यदि स्कूल आठ सप्ताह के लिए बंद थे, तो सात से अधिक देशों में, पढ़ाई का नुकसान गणित के लिए एक स्कूल वर्ष के 30% और रीडिंग के लिए औसतन 35% के बराबर था। लेकिन फ्रांस में, कक्षा 6 के छात्रों के बीच पढ़ने और गणित के परिणामों में सुधार हुआ।

इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण भिन्न होते हैं। अमेरिका में, 12 राज्यों में कक्षा 3 से 8 के छात्रों की परीक्षा उत्तीर्ण दरों के विश्लेषण से पता चला है कि व्यक्तिगत से पूरी तरह से हाइब्रिड या वर्चुअल मोड में जाने से गणित में औसतन 10 प्रतिशत अंक और अंग्रेज़ी में 4 प्रतिशत अंक की कमी हुई है। पूरी तरह से हाइब्रिड या वर्चुअल मोड में स्विच करने से ब्लैक या हिस्पैनिक छात्रों वाले जिले में 4 प्रतिशत अंक कम हो गए, लेकिन 50% ब्लैक और हिस्पैनिक छात्र आबादी वाले जिले में 9 प्रतिशत अंक कम हो गए।

निम्न और मध्यम आय वाले देशों में प्रत्यक्ष सीखने के आकलन की कमी है। साओ पाउलो, ब्राजील में, माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने कोई महामारी न होने पर स्कूल में जो वे सीखते, का केवल 27.5% ही सीखा; जिन छात्रों के स्कूल फिर से खुल गए, उन्हें सीखने का कम नुकसान हुआ। कोलंबिया में, छात्रों ने पिछले वर्ष से पांच अंक कम प्रदर्शन किया, जो एक स्कूल वर्ष का लगभग एक-चौथाई बैठता है। दक्षिण अफ्रीका में, कक्षा 2 और 4 के छात्रों ने महामारी से पहले के अपने साथियों की तुलना में, 2020 में पढ़ने का कौशल एक वर्ष में 57% और 81% के बीच खो दिया।

दक्षिण एशिया में नागरिकों के नेतृत्व वाली शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट के आकलनों से पता चलता है कि शुरुआती कक्षा में सीखने के स्तर में गिरावट आई है। भारत के ग्रामीण कर्नाटक राज्य में, कक्षा 2

पाठ पढ़ने में सक्षम छात्रों का प्रतिशत सभी कक्षाओं के छात्रों के बीच गिर गया, लेकिन 2018 और 2020 के बीच कक्षा 4 के छात्रों (33% से 18%) में गिरावट सबसे खराब थी। पाकिस्तान में, 16 जिलों के सर्वेक्षण में कक्षा 1 और 3 में बुनियादी कौशल में एक-समान सीखने की कमी पाई गई, लेकिन यह कक्षा 5 में नहीं थी।

इन अलग-अलग सबूतों को जोड़ने पर इस बात की पुष्टि होती है कि स्कूल बंद होने से छात्रों पर सीखने का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यदि नुकसान को एसडीजी 4 न्यूनतम प्रवीणता स्तर के संदर्भ में परिभाषित किया जाए, तो इसका प्रभाव निम्न-आय वाले देशों की तुलना में मध्यम-आय वाले देशों में अधिक हो सकता है, जहां प्रारंभिक स्तर बहुत कम थे, या उच्च-आय वाले देशों में, जहां स्कूल कम अवधि के लिए बंद रहे और छात्रों के पास ऑनलाइन सीखने की अधिक पहुंच थी। फिर भी, कई पहलू अज्ञात हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या सीखने का स्तर वापस बढ़ेगा या कोविड-19 का सीखने पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा।

परिणामों को कम करने के लिए, देशों ने शैक्षणिक वर्ष को बढ़ाया या समायोजित किया है और पाठ्यक्रम या कौशल के कुछ क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है। दो-तिहाई देशों ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सुधार उपायों को लागू करने की जानकारी दी। फिलीपींस में, शिक्षा विभाग ने छह सप्ताह तक सुधार कक्षाएं चलाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए, जो ऐसे छात्रों के लिए चलाई गईं, जिन्होंने साल के अंत में होने वाली परीक्षाओं में 75% से कम अंक प्राप्त किए थे। इंग्लैंड (ब्रिटेन) में राष्ट्रीय शिक्षण कार्यक्रम 6 मिलियन वंचित छात्रों के लिए 15 घंटे के शिक्षण पाठ्यक्रमों का समर्थन करता है।

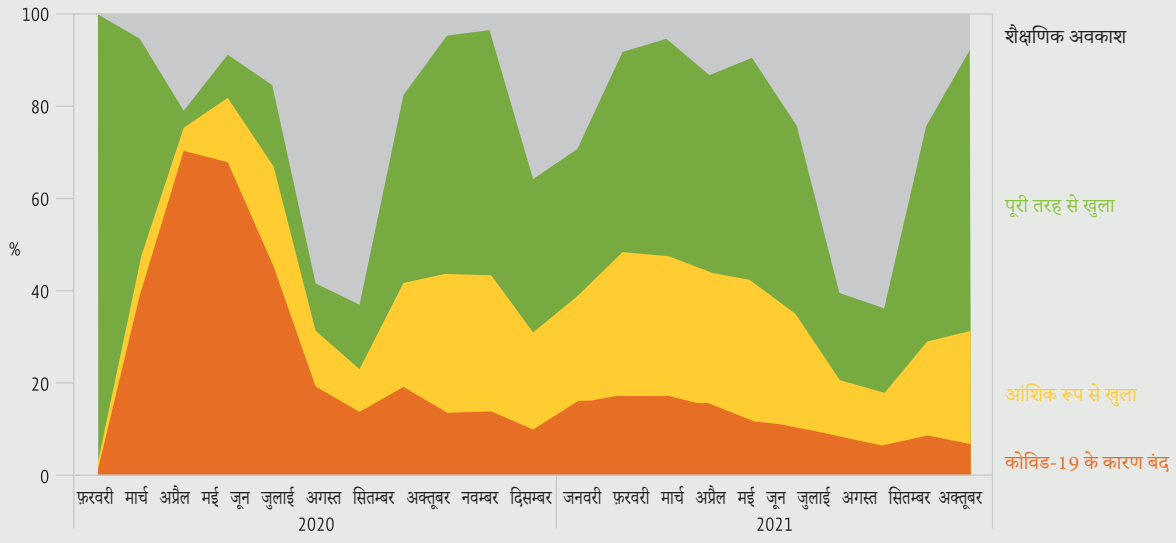
महामारी ने **शिक्षकों** के लिए अभूतपूर्व चुनौतियां भी पेश की हैं। स्कूल बंद होने से कई शिक्षक दूरस्थ शिक्षा के लिए अभ्यस्त नहीं थे, अपनी भूमिका के बारे में अनिश्चित थे और तकनीक से अपरिचित थे। 165 देशों में 20,000 से अधिक शिक्षकों के एक सर्वेक्षण में, 39% ने कहा कि महामारी के दौरान उनकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति प्रभावित हुई थी। दूसरी ओर, 50% लोगों ने कहा कि वे अपने पेशे के बारे में अधिक उत्साहित महसूस किया। संकट ने शिक्षक शिक्षा की सामग्री में आवश्यक बदलाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तकनीकी ज्ञान से परे, शिक्षकों को छात्रों की नई सामाजिक-भावनात्मक और शैक्षणिक आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है।

सतत विकास और **वैश्विक नागरिकता** के लिए शिक्षा इस ग्रह की उन चुनौतियों का जवाब है जो तेजी से आपस में जुड़ी हैं लेकिन जिसका भविष्य दांव पर है। फिर भी कोविड-19 ने एकजुटता और बहुपक्षवाद के आदर्शों को आगे बढ़ाने में शिक्षा प्रणालियों की विफलताओं को उजागर किया है, और देशों के भीतर और उनके बीच बढ़ती असमानता ने नैतिक समस्याओं को जन्म दिया है। वैक्सीन राष्ट्रवाद से लेकर दूसरे देशों से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने तक, दुनिया ने कई विपरीत प्रतिक्रियाएं देखी हैं। कोविड-19 ने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक होने पर भी ध्यान दिलाया है।

चित्र 4:

20 महीनों में, स्कूल कम से कम 55% दिनों के लिए आंशिक रूप से बंद रहे

स्कूल खुलने की स्थिति के अनुसार, फरवरी 2020 से अक्तूबर 2021 माह तक दिनों का अनुपात



जीईएम सांख्यिकी लिंक: https://bit.ly/GEM2021_Summary_fig4

स्रोत: यूआईएस (2021सी)।

सामाजिक स्तर पर संक्रमण के उतार-चढ़ाव के साथ स्कूल बंद होने और फिर से खोलने का अंतिम प्रभाव अनिर्णायक रहता है। लेकिन **सीखने के वातावरण** में संक्रमण के जोखिम को मास्क लगाकर, सामाजिक दूरी का पालन करके और हाथ धोने से लेकर वस्तुओं को साझा करने को हतोत्साहित करने और बार-बार छूने वाली सतहों को कीटाणुरहित करने के उपाय अपनाकर कम किया जा सकता है। बेहतर आबोहवा के लिए कम-तकनीकी समाधानों में बाहरी खुले स्थानों का उपयोग करना और खिड़कियां खोलना शामिल है, बशर्ते यह मौसम के अनुसार उपयुक्त हो। कम आय वाले 10% से कम देशों ने सभी शिक्षार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त साबुन, साफ पानी, मास्क, और साफ-सफाई और स्वच्छता सुविधाओं जैसे पर्याप्त बुनियादी उपायों की सूचना दी; उच्च आय वाले देशों की हिस्सेदारी 96% थी।

कुछ साक्ष्य सामने आ रहे हैं कि महामारी और उसके प्रकोप के कारण सरकारी राजस्व में कमी होगी और अन्य क्षेत्रों में राजस्व की मांग के बढ़ने से शिक्षा **वित्तपोषण** कम कर दिया जाएगा। यूआईएस द्वारा 71 देशों से एकत्र किए गए आंकड़े बताते हैं कि कुल खर्च में औसत शिक्षा का हिस्सा 2019 में 14.1% से घटकर 2021 में 13.5% हो गया।

बाल शिक्षा में, यहां तक कि जहां दूरस्थ शिक्षा उपलब्ध थी, चुनौतियों में शिक्षक प्रशिक्षण की कमी, छोटे बच्चों के लिए दूरस्थ शिक्षा को अपनाना, बाल विकास की निगरानी और मूल्यांकन करना तथा पर्याप्त समर्थन न मिलने के कारण घरेलू वातावरण से निपटना शामिल था। सुविधाओं के बंद होने और सीमित संवाद ने बच्चों को उनके घरों से बाहर सामाजिक और प्रदर्शन में सुधान करने वाली अनेक गतिविधियों से वंचित कर दिया।

तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रभावित हुआ क्योंकि 80% कार्यक्रम व्यावहारिक और परस्पर कौशल पर केंद्रित थे, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से हासिल किया जाना चाहिए था। शिक्षकों को तैयार करना एक प्रमुख मुद्दा रहा है, क्योंकि उनमें दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने की क्षमता नहीं थी, जबकि उनके मानक शिक्षा कार्यक्रम बाधित थे। दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के लिए कई पहलुओं का उपयोग करना और केवल उच्च-तकनीकी समाधानों पर निर्भर नहीं रहना भी महत्वपूर्ण है। साथ ही, इससे उबरने के उदाहरण भी हैं जहां प्रशिक्षण अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों का सहायता प्रदान करता है।

अन्य शिक्षा स्तरों की तुलना में **उच्च स्तरीय शिक्षा** में दूरस्थ शिक्षा का अनुभव अधिक था। 53 देशों के एक सर्वेक्षण में, 3 देशों ने पूरी तरह से ऑनलाइन उच्च शिक्षा में स्विच करने की सूचना दी, 19 देशों में मुख्य रूप से ऑनलाइन प्रावधान थे और 28 देशों ने दूरस्थ और आमने-सामने सीखने की एक मिश्रित अवधारणा का उपयोग किया। मध्यम-आय वाले देशों, कोलंबिया से मिस्र और चीन से लेकर रूसी संघ तक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किए। लेकिन उप-सहारा अफ्रीकी छात्रों के एक सर्वेक्षण में, दूरस्थ शिक्षा विकल्प प्रदान करने वाले संस्थानों में केवल 39% नामांकित थे। यूरोपीय संघ के देशों में, अध्ययन के दौरान काम करने वाले 41% छात्रों में से 29% ने अस्थायी रूप से और 12% ने स्थायी रूप से अपनी नौकरी खो दी।

लोकप्रिय अंग्रेजी भाषी अंतरराष्ट्रीय छात्र गंतव्य स्थल, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका ने आने वाली **छात्र गतिशीलता** में कमी का अनुभव किया। ऑस्ट्रेलिया में एक-तिहाई छात्रों के अंतर्राष्ट्रीय होने के कारण, इसने उच्च शिक्षा संस्थानों को गंभीर वित्तीय संकट में डाल दिया। छात्र और स्नातक मेजबान देशों में फंसे हुए थे जबकि वे अपने देश लौटने की उम्मीद कर रहे थे।

प्रौढ़ साक्षरता और संख्यात्मक कौशल स्वास्थ्य जानकारी और टीकाकरण अभियानों को प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं तथा ये सार्वजनिक आपातकालीन प्रतिक्रियाओं और पुनर्निर्माण योजनाओं का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। भारत में, प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम में भाग लेने वाली महिलाओं को अपनी अनपढ़ साथियों की तुलना में अधिक कोविड-19 ज्ञान था। कोविड-19 के बारे में भ्रामक सूचना को दूर करने का सबसे सुसंगत तरीका संख्या ही थी। फिर भी महामारी से पहले, प्रारंभिक साक्षरता कार्यक्रमों के लिए दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने का तरीका लोकप्रिय नहीं था। ब्राजील में, एक विनियम ने स्पष्ट किया कि प्राथमिक पाठ्यक्रम वाली कक्षाओं को केवल व्यक्तिगत रूप से ही चलाया जाए।

लक्ष्य 4.1. प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा

महामारी से पहले, 260 मिलियन बच्चे, किशोर और प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल उम्र के युवा स्कूल नहीं जाते थे। एक दशक में यह आंकड़ा शायद ही बढ़ा था। जीईएम रिपोर्ट और यूआईएस के बीच एक सहयोगी परियोजना प्रशासनिक और घरेलू सर्वेक्षण स्रोतों को एकीकृत और पृथक करने, प्रशासनिक डेटा में कमियों को दूर करने और एक सुसंगत समय श्रृंखला विकसित करने के लिए चलाई जा रही है। यह पूर्णता दर का अनुमान लगाने के लिए कई स्रोतों को समेकित करते हुए जीईएम रिपोर्ट टीम के काम पर आधारित है। एक नई वेबसाइट (www.education-estimates.org) देशों को यह दृष्टिकोण अधिक सुलभ तरीके से प्रदान करती है। उप-सहारा अफ्रीका को छोड़कर, सभी क्षेत्रों में प्राथमिक पूर्णता दर 90% तक पहुंच रही है या उससे अधिक है, जहां तीन में से केवल दो बच्चे प्राथमिक स्कूल पूरा करते हैं, हालांकि यदि बहुत देर से अंतिम कक्षा में पहुंचने वालों को शामिल किया जाए तो यह दर 65% से बढ़कर 76% हो जाती है **(चित्र 5)**। उप-सहारा अफ्रीका में, प्राथमिक विद्यालय में 23% बच्चे और निम्न माध्यमिक विद्यालय में 31% किशोर काफी बड़ी आयु के हैं, जो यह बताता है कि इस क्षेत्र में समय पर और अंतिम पूर्णता दर के बीच सबसे बड़ा अंतर क्यों है।.

अंतर्राष्ट्रीय गणित और विज्ञान अध्ययन (टीआईएमएसएस) में रुझान द्वारा कवर किए गए देशों के वैश्विक समूह में, न्यूनतम स्तर की प्रवीणता प्राप्त करने वाले छात्रों की हिस्सेदारी में 2015 और 2019 के बीच औसत वार्षिक वृद्धि कक्षा 4 में 0.3 प्रतिशत अंक और कक्षा 8 में 0.5 प्रतिशत अंक थी। इन औसत से ऊपर वाले देशों में चिली भी शामिल है, जहां की हिस्सेदारी 2003 में 41% से बढ़कर 2011 में 57% और 2019 में 70% हो गई, अर्थात् इसकी विकास दर औसत से कम से कम तीन गुना तेज थी। अन्य जगहों पर, जैसे कि जॉर्डन और रोमानिया में, बहुत कम या कोई वृद्धि नहीं हुई थी। अंतिम 10% तक पहुंचना अच्छे संसाधन वाले समूहों में भी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। अमेरिका में, 86% छात्रों ने 1995 में टीआईएमएसएस निम्न अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क हासिल किया और 2019 में यह 87% रहा; न्यूजीलैंड में, शेयर 1995 में 89% से लगातार गिरकर 2019 में 82% हो गया।

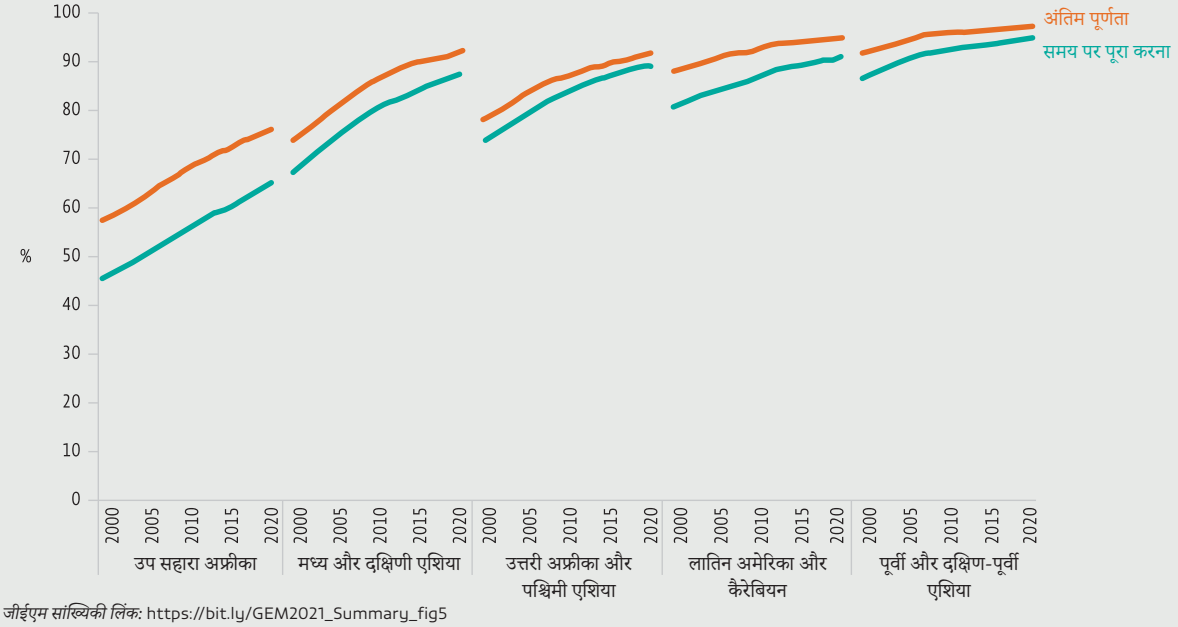
लक्ष्य 4.2. बचपन

36 से 59 महीने की उम्र के बच्चों के बाल्यकाल विकास सूचकांक के आंकड़े बताते हैं कि संपत्ति का अंतर ज्यादातर स्थिर या बढ़ा हुआ है। इस संकेतक की कार्यप्रणाली, जो छोटे बच्चों के स्वास्थ्य, सीखने और मनोसामाजिक स्थिति में हुए विकास का प्रतिशत एकत्र करती है, को पूरी तरह से अद्यतन किया गया है। पढ़ाई की शुरुआत घर से होती है। वर्ष 2012-19 में, निम्न और मध्यम आय वाले देशों के एक समूह में 62% बच्चे घर में एक वयस्क द्वारा चार या अधिक गतिविधियों में लगे हुए थे। गाम्बिया, सिएरा लियोन और टोगो में यह प्रतिशत 20% से नीचे था। इन गतिविधियों को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण बाधा पुस्तकों की उपलब्धता

चित्र 5:

समय पर स्कूल पूरा होने का संकेतक काफी कम आंकता है कि अंततः कितने बच्चे स्कूल पूरा करते हैं, विशेषकर उप-सहारा अफ्रीका में

क्षेत्र के अनुसार पूर्णता दर और अंतिम पूर्णता दर, 2000-20



जीईएम सांख्यिकी लिंक: https://bit.ly/GEM2021_Summary_fig5

स्रोत: घरेलू सर्वेक्षण डेटा का जीईएम रिपोर्ट टीम विश्लेषण।

है जिन्हे संयुक्त रूप से पढ़ना पड़ता है। औसतन, 5 साल से कम उम्र के एक-चौथाई से भी कम बच्चों के पास घर पर कम से कम तीन किताबें थीं। आधे देशों में, 10 में से 1 से भी कम बच्चे के पास; उप-सहारा अफ्रीका के 8 देशों में, 1% से भी कम बच्चों के पास किताबें उपलब्ध थीं।

शिक्षा का अधिकार जन्म से ही शुरू हो जाता है। जब तक बच्चा 3 साल की उम्र तक पहुंचता है, तब तक उसके दिमाग का 90% हिस्सा विकसित हो चुका होता है। प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा कार्यक्रमों में 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की भागीदारी सीमित होती है, हालांकि यह कई मध्यम और उच्च आय वाले देशों में 0 से 1 वर्ष की आयु के लिए 20% से अधिक और 2 वर्ष की आयु के लिए 60% से अधिक तक पहुंच जाती है। उच्च आय वाले देशों में भी, बाल देखभाल और शिक्षा तक पहुंच अभी भी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर बहुत अधिक निर्भर है। फ्रांस और आयरलैंड में, गरीब और अमीर परिवारों में 0 से 2 साल के बच्चों की भागीदारी में अंतर 50 प्रतिशत से अधिक है। वैश्विक स्तर पर, 2020 में समाप्त होने वाले स्कूल वर्ष में आधिकारिक प्राथमिक प्रवेश आयु से एक वर्ष पहले 75% बच्चों का प्री-प्राइमरी शिक्षा में दाखिला हुआ था। समायोजित कुल नामांकन दर निम्न आय वाले देशों (45%) में उच्च आय वाले देशों (91%) की तुलना में आधी थी।

लक्ष्य 4.3 तकनीकी, व्यावसायिक, उच्च स्तरीय और प्रौढ़ शिक्षा

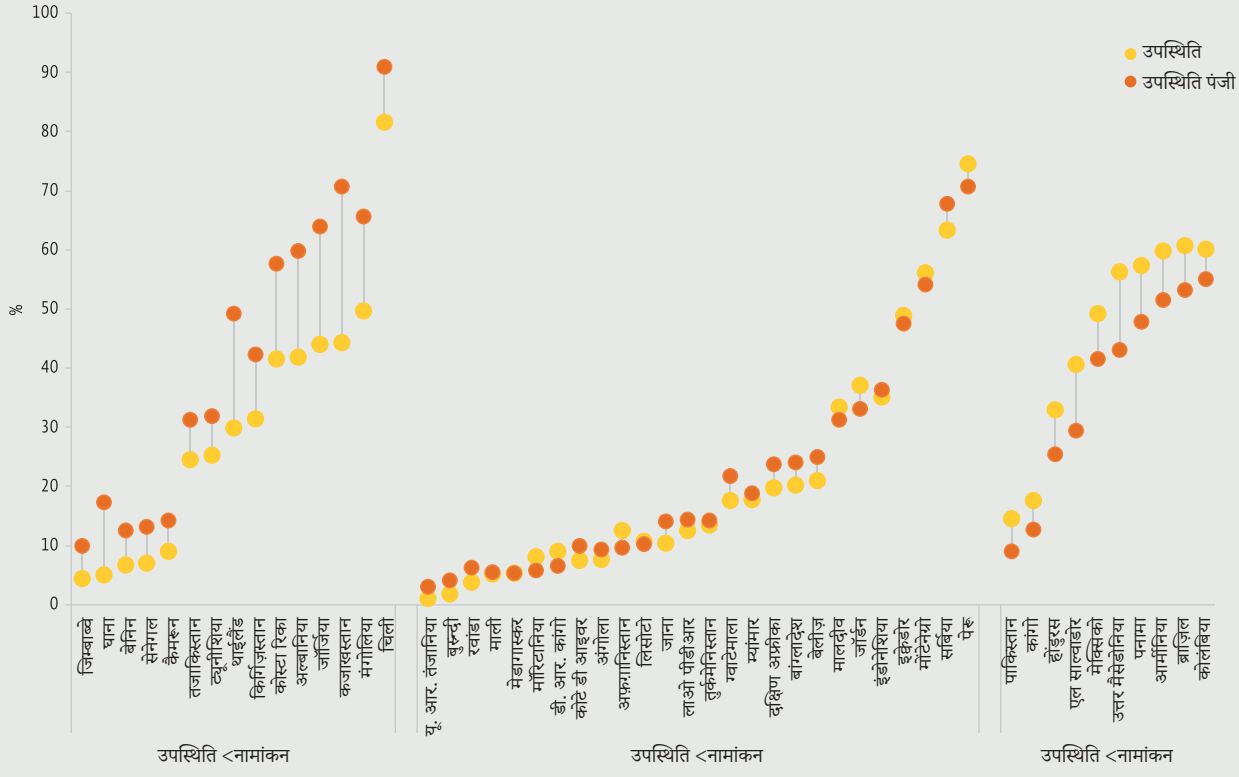
टीवीईटी अभी भी कई देशों में कम और अक्सर उपेक्षित है, हालांकि आर्मेनिया, ब्राजील, बुरुंडी, कोस्टा रिका, इंडोनेशिया और उरुग्वे सहित देशों ने पिछले 15 वर्षों में भागीदारी दरों में काफी वृद्धि की है। व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा एक आकर्षक विकल्प नहीं लग सकता है, यदि सामान्य माध्यमिक प्रमाणपत्र से भिन्न, कोई व्यावसायिक डिप्लोमा सीधे उच्च स्तरीय शिक्षा में जारी रखने का विकल्प प्रदान नहीं करता है, जैसा कि एक-चौथाई देशों में होता है। इसके विपरीत, 30% देशों में, सभी व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालय के स्नातक उच्च स्तरीय शिक्षा तक सीधे पहुंच प्राप्त करते हैं।

उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए वैश्विक सकल दाखिला अनुपात 39% था, जो 2000 के बाद से प्रतिवर्ष लगभग 1 प्रतिशत की औसत वृद्धि जारी रखे जुए है। ये प्रशासनिक डेटा हमेशा उपस्थिति संबंधी सर्वेक्षण

चित्र 6:

उच्च स्तरीय शिक्षा दाखिला डेटा वास्तविक उपस्थिति को अधिक या कम आंक सकता है

उच्च स्तरीय शिक्षा में कुल उपस्थिति और दाखिला अनुपात, 2015-19



जीईएम सांख्यिकी लिंक: https://bit.ly/GEM2021_Summary_fig6

स्रोत : यूआईएस डेटाबेस।

के आंकड़ों से मेल नहीं खाता है (**चित्र 6**)। दाखिला उपस्थिति को कम आंक सकता है यदि कई छात्र ऐसे संस्थानों में जाते हैं जिन्हें आधिकारिक आंकड़ों में नहीं गिना जाता है क्योंकि वे मान्यता-प्राप्त नहीं होते हैं। इसके विपरीत, यदि कई छात्रों को केवल नाममात्र के लिए नामांकित किया जाता है, तो यह नामांकन उपस्थिति को कम कर सकता है, विशेष रूप से जहां ट्यूशन मुफ्त है और छात्र की स्थिति सब्सिडी वाली सेवाओं से प्राप्त होती है। इसके अलावा, प्रशासनिक डेटा उच्च माध्यमिक स्नातक आयु के तुरंत बाद पांच वर्ष की नाममात्र आयु सीमा से संबंधित है, लेकिन उच्च आयु में उच्च स्तरीय अध्ययन आम बात है, जैसे कि उप-सहारा अफ्रीका में।

आजीवन दृष्टिकोण से देखा जाए तो उच्च स्तरीय शिक्षा कभी भी सस्ती नहीं रही है। उच्च स्तरीय शिक्षा में लागत साझा करने का आर्थिक मामला संभावित रूप से उन भावी छात्रों पर निर्भर करता है जिनके सामने ऋण लेने की कोई समस्या नहीं है। विभिन्न प्रकार के छात्र ऋण 70 से अधिक देशों में उपलब्ध हैं और जिनका ट्रिलियन-डॉलर का बाजार है। कई देशों में, छात्र ऋण चुकाने के लिए अपेक्षित उधारकर्ताओं की आय का अनुपात अत्यधिक है, विशेषकर जो सबसे कम समृद्ध स्नातक हैं। सबसे बेहतर नीतिगत सुधार में व्यापक तौर पर समय-आधारित ऋण की चुकौती की बजाय आय-आधारित आकस्मिक ऋण देना शामिल है।

अधिकांश उच्च आय वाले देशों में, नियोक्ता वयस्क शिक्षा और प्रशिक्षण के सबसे बड़े प्रदाता हैं, जो उन व्यक्तियों के लिए नीतियां बनाते हैं जो श्रम बाजार से बाहर हैं। यहां तक कि रोजगार-प्राप्त लोगों के लिए भी, प्रशिक्षण प्राप्त करने का समय प्रायोजकता जितना महत्वपूर्ण हो सकता है, जो अध्ययन अवकाश कार्यक्रमों के रूप में सार्वजनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता को दर्शाता है। पूर्व से पश्चिम तक के छह उच्च आय वाले देशों के आंकड़े बताते हैं कि वयस्क शिक्षा महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक, विशेषकर अधिक शिक्षित लोगों के बीच बार-बार किया जाने वाला प्रयास है।

लक्ष्य 4.4. कामकाज में कौशल

डेटा वाले 91 में से केवल 10 देशों में अधिकांश वयस्कों ने रिपोर्ट किया है कि 9 में से कम से कम 5 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) कौशल की वैश्विक आधार पर निगरानी की जाती है। लगभग आधे देशों में, अधिकांश वयस्कों के पास कोई कौशल नहीं है। अधिकांश निम्न और मध्यम आय वाले देशों में, कुछ युवा लोग जिन्होंने निम्न माध्यमिक विद्यालय पूरा नहीं किया है, के पास कोई न कोई आईसीटी कौशल है। इराक में, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और सिएरा लियोन, यहां तक कि सबसे शिक्षित औसत, नौ कौशल में से दो से भी कम है। उपकरणों और इंटरनेट तक पहुंच भी एक अन्य बाधा है: चाड में 20 से 24 साल के बच्चों में भी, 98% महिलाओं और 90% पुरुषों ने कभी भी इंटरनेट का उपयोग नहीं करने की सूचना दी; संबंधित शेयर लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में 61% और 63% और ट्यूनीशिया में 36% और 31% थे।

कम्प्यूटेशनल विचारधारा को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। फ़िनलैंड ने कक्षा 1 से पाठ्येतर गतिविधि के रूप में एल्गोरिथम विचारधारा और प्रोग्रामिंग को अनिवार्य बना दिया है। 2018 में आठ उच्च आय वाले देशों की समीक्षा में, स्कूल से संबंधित कार्यों के लिए स्कूल में आईसीटी का अधिक बार उपयोग करने वाले छात्रों ने अपने साथियों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त नहीं किए, और प्रोग्रामिंग का अनुभव रखने वाले छात्र इस कौशल को नॉन-प्रोग्रामिंग में परिवर्तित करने में सक्षम नहीं थे।

वित्तीय साक्षरता आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में आजीविका के लिए और सामान्य रूप से वयस्क जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है, लेकिन हर किसी को स्कूल में महत्वपूर्ण वित्तीय अवधारणाओं को सीखने का अवसर नहीं मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन के लिए 2018 कार्यक्रम में एक वैकल्पिक वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल शामिल था, जिसका उपयोग 20 प्रतिभागी शिक्षा प्रणालियों द्वारा किया गया था। इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय शिक्षा आमतौर पर गणित में शामिल होती है, आमतौर पर एक गैर-वैकल्पिक विषय होने के बावजूद, सभी भाग लेने वाले देशों में लड़कियों द्वारा वित्तीय विषयों से संबंधित कक्षा गतिविधियों की रिपोर्ट करने की संभावना कम थी।

लक्ष्य 4.5 समानता

लैंगिक असमानता एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है, भले ही विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न स्थानों पर अनेक प्रकार की चुनौतियों को समझने के लिए अति सूक्ष्म अंतर की आवश्यकता हो। उच्च माध्यमिक शिक्षा वह स्तर है जहां किशोर लड़कियां व्यापक रूप से वंचित हो सकती हैं (जैसे बेनिन, चाड और नाइजर में) लेकिन उनके पक्ष में परिस्थितियों में तेजी से बदलाव से उनके द्वारा इसका लाभ उठाने की भी संभावना है। यह उन अनेक देशों में हो रहा है, जो कंबोडिया, कांगो, गाम्बिया, घाना, मलावी और रवांडा सहित विशिष्ट क्षेत्रों में अपने साथियों के सापेक्ष एसडीजी 4 प्राप्त करने से सबसे पीछे हैं।

संपन्नता, जिसे घरेलू स्तर पर मापा जाता है, हमेशा बच्चों के वंचित रहने का कारण नहीं बनती। कई देशों में, 10% वंचित बच्चे सबसे अमीर घरों में हैं और सबसे गरीब घरों में 30% से अधिक बच्चे वंचित नहीं हैं। वंचित बच्चों का स्तर शिक्षा के परिणाम को प्रभावित करने का एक अन्य ठोस कारण हो सकता है।

गैर-सरकारी सशस्त्र समूहों द्वारा नियंत्रित स्कूलों में बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। इन समूहों के पास चुनिंदा शिक्षा प्रदान करने के कई कारण हैं, चाहे प्रत्यक्ष नियंत्रण द्वारा, चुनिंदा हस्तक्षेप के माध्यम से, जैसे पाठ्यक्रम में, या मौजूदा प्रदाताओं को काम करने की अनुमति देकर। शिक्षा नागरिकों द्वारा मांगी जाने वाली सबसे बहुमूल्य सेवाओं में से एक है; इसे प्रदान करने में विफलता नाराजगी में तब्दील हो सकती है।

शिक्षा में भाषाई विविधता की चुनौतियां हैं। चाड, गाम्बिया और टोगो सहित पश्चिमी और मध्य अफ्रीकी देशों में, 7 से 14 वर्ष की आयु के

5% से अधिक बच्चे घर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा नहीं बोलते हैं। भाषाई डेटा स्रोतों, स्कूल-आयु जनसंख्या अनुमानों और दाखिले की दरों सहित भाषा का माध्यम नीति को मिलाने से एक तथ्य सामने आया कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 37% बच्चे अपनी घरेलू भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में सीखते हैं: 27% अल्पसंख्यक लिखित भाषा और 10% कम आम भाषा बोलते हैं, प्रत्येक के अपेक्षाकृत कम बोलने वाले थे।

लक्ष्य 4.6 साक्षरता और संख्या

विश्व स्तर पर, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों में, 83% महिलाएं और 90% पुरुष साक्षर हैं, साक्षरता के दोहरे वर्गीकरण के संदर्भ में - 7 प्रतिशत अंक का अंतर है। उप-सहारा अफ्रीका में चार में से एक से अधिक युवतियां निरक्षर हैं, जहां युवा महिला साक्षरता दर में प्रतिवर्ष एक प्रतिशत से भी कम की वृद्धि हुई है। विश्व स्तर पर, 1999 के बाद से पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में निरक्षर महिलाओं की संख्या में गिरावट उप-सहारा अफ्रीका में वृद्धि से लगभग समायोजित हो गई है। इसके अलावा, एक धारणा है कि सभी माध्यमिक स्कूल के छात्र साक्षर हैं, इसका मतलब है कि वास्तविक साक्षरता स्तर को पहले से कम करके आंका गया है। हाल के सर्वेक्षण के आंकड़ों के साथ 18 देशों में लगभग आधे निम्न माध्यमिक शिक्षार्थी साक्षरता के बुनियादी स्तर प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिसे एक साधारण वाक्य को पढ़ने में सक्षम होने के रूप में परिभाषित किया गया है (**चित्र 7**)।

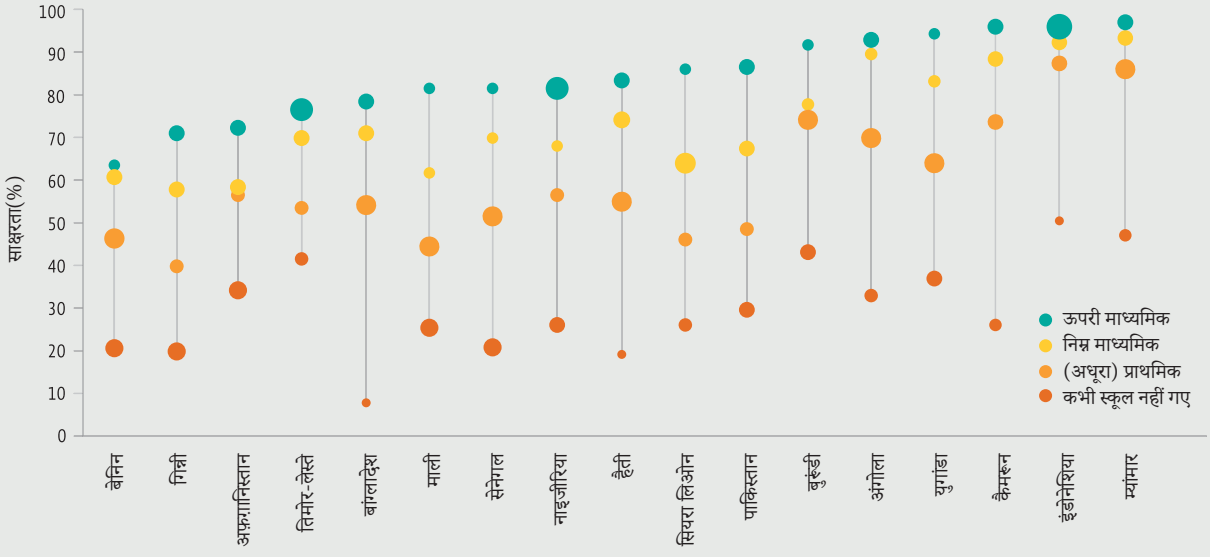
इसके विपरीत वास्तविकता यह है कि यदि कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह निरक्षर है, जो स्कूल के बाहर साक्षरता हासिल करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। अनुमानित निरक्षर आबादी के संबंध में, अनौपचारिक आईएससीईडी 1 कार्यक्रमों में वयस्क नामांकन बोलीविया, होंडुरास, मोज़ाम्बिक, कतर और सूरीनाम में 1% या उससे कम है, बहरीन और पेरू में 2%, कोलंबिया और थाईलैंड में 3%, में 4% है सऊदी अरब और डोमिनिकन गणराज्य में 8% है।

साधारण संख्यात्मक कौशल पर भी डेटा बहुत कम उपलब्ध है। बुनियादी संख्यात्मकता के एक प्रॉक्सी माप की गणना उनकी उम्र को सही ढंग से बताते हुए प्रतिशत के रूप में की जा सकती है, जो सरल, कम पूर्णांकों के साथ काम करने की क्षमता को दर्शाता है। जबकि अधिकांश, यहां तक कि सबसे गरीब भी, इस दहलीज को पार करते हैं, यह उपाय ऐतिहासिक संख्यात्मक प्रवृत्तियों की जांच के लिए उपयुक्त है। घरेलू सर्वेक्षण और

चित्र 7:

माध्यमिक विद्यालय छोड़ने वालों को भी यह नहीं माना जा सकता है कि उन्होंने साक्षरता हासिल कर ली है

चयनित देशों में स्कूल जाने वाले 20 से 24 आयु वर्ग में साक्षरता दर, 2015-19



टिप्पण: डॉट का आकार प्रत्येक प्राप्ति स्तर पर जनसंख्या के आकार का समान अनुपात है।

जीईएम सांख्यिकी लिंक: https://bit.ly/GEM2021_Summary_fig7

स्रोत: डीएचएस डेटा का जीईएम रिपोर्ट टीम विश्लेषण।

जनसंख्या जनगणना के आंकड़ों के विश्लेषण से 1960 और 2010 के बीच पैदा हुए सहकर्मियों की संख्या का पता 42 उप-सहारा अफ्रीकी देशों में लगाया जा सकता है। समय के साथ सुधार मामूली रहा है और सबसे गरीब लोगों के बीच कायम नहीं रहा है। अफ्रीका में संख्या में समग्र वृद्धि लगभग पूरी तरह से स्कूल की बढ़ती भागीदारी के कारण थी।

लक्ष्य 4.7 सतत विकास और वैश्विक नागरिकता

लक्ष्य 4.7 एसडीजी 4 की परिवर्तनकारी महत्वाकांक्षाओं तक पहुंचने के लिए शिक्षार्थियों को क्या सीखने की जरूरत है, इसका समाधान करने में एसडीजी 4 एजेंडा से परे जाकर कार्य करता है। जीवन कौशल-आधारित एचआईवी और यौन शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों की हिस्सेदारी प्राय: कम होती है, विशेषकर प्राथमिक स्तर, जैसे बुर्किना फासो में 2.5% प्राथमिक विद्यालय और नाइजर में 6%। फिर भी लैंगिकता शिक्षा पर संशोधित संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मार्गदर्शन में सिफारिश की गई है कि 9 से 12 वर्ष की आयु के शिक्षार्थियों द्वारा अनुभव किए जाने से पहले यौवन और मासिक धर्म को कवर किया जाए। यूनेस्को की लैंगिकता शिक्षा समीक्षा और आकलन उपकरण व्यापक यौन शिक्षा पर हाल की वैश्विक प्रगति रिपोर्ट को दर्शाता है। 24 देशों में, केवल 3 देशों का मूल्यांकन 9 से 12 वर्ष की आयु के शिक्षार्थियों के लिए यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर 'उन्नत' पाठ्यक्रम सामग्री प्रदान करने के रूप में किया जाता है, और 5 देशों में 'स्थापित' सामग्री के रूप में मूल्यांकन किया जाता है।

23 उच्च-मध्यम और उच्च आय वाले देशों में 2016 के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और नागरिकता शिक्षा अध्ययन में पाया गया कि वैश्विक नागरिकता से संबंधित मुद्दों की पर्याप्त समझ रखने वाले छात्रों का प्रतिशत डोमिनिकन गणराज्य, लातविया और नीदरलैंड में लगभग 40% से लेकर क्रोएशिया, कोरिया गणराज्य और स्वीडन में लगभग 70% था। 2019 टीआईएमएसएस ने दिखाया कि केवल 30% छात्र ही पर्यावरण विज्ञान में दक्षता हासिल कर पाए हैं। जलवायु परिवर्तन शिक्षा का उद्देश्य आबादी को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने, समाधान करने, कम करने और अनुकूल बनाने में मदद करना है। जीईएम रिपोर्ट तथा निगरानी एवं मूल्यांकन जलवायु संचार और शिक्षा परियोजना द्वारा जलवायु परिवर्तन संचार और शिक्षा पर देश प्रोफाइल की एक नई श्रृंखला तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है। 20 देशों के प्रोफाइल के पहले समूह में सभी क्षेत्रों और देश के आय समूहों को शामिल किया गया है। 50 प्रोफाइल का दूसरा समूह 2022 में प्रकाशित होने वाला है। प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि केवल 40% राष्ट्रीय शिक्षा कानूनों और 45% शिक्षा क्षेत्र की योजनाओं या कार्यनीतियों में जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

लक्ष्य 4.क. शिक्षा सुविधाएं और सीखने का माहौल

अच्छी पढ़ाई तब तक नहीं हो सकती है जब तक माहौल उपयुक्त न हो, लेकिन यदि यह बच्चे के स्वास्थ्य माहौल के लिए खतरा है तब तो यह बिल्कुल नहीं हो सकती। सुरक्षित स्कूल घोषणा, सशस्त्र संघर्ष के दौरान छात्रों, शिक्षकों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों को हमले से बचाने के लिए एक अंतर-सरकारी राजनीतिक प्रतिबद्धता, अब 112 राज्यों द्वारा समर्थित है। सबूत लगातार मिलते जा रहे हैं कि शारीरिक दंड न केवल बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करता है, बल्कि शिक्षा के परिणामों को भी प्रभावित करता है। 156 देशों के स्कूलों में अब शारीरिक दंड पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

स्कूल ही एकमात्र ऐसा स्थान हो सकता है जहाँ कुछ बच्चों को पानी, स्वच्छता और साफ-सफाई की सुविधा हो। लाइबेरिया में, कुछ घरों में स्वच्छता सुविधाएं हैं जो बुनियादी अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करती हैं, लेकिन 69% स्कूल ऐसा करते हैं। हालांकि, मुख्य रूप से दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित छोटे स्कूलों द्वारा बड़े स्कूलों की तुलना में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता के मानदंडों को पूरा करने की संभावना कम मानी जा सकती है। काबो वर्डे में, 2018 में 22% प्राथमिक स्कूलों में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा का अभाव था। हालांकि, सबसे छोटे 22% प्राथमिक स्कूलों में प्राथमिक दाखिला का केवल 2% हिस्सा था। विश्व स्तर पर, बुनियादी सुविधाओं के बिना स्कूलों में जाने वाले बच्चों की हिस्सेदारी स्कूलों के हिस्से की तुलना में काफी कम होने की संभावना है।

भौतिक सुविधाओं से परे, अन्य पहलू जैसे स्कूल कैलेंडर की व्यवस्था - सप्ताह और वर्षों में निर्देश के दिनों के वितरण से लेकर स्कूल दिवस की अवधि और व्यवस्था तक - शिक्षा प्रणालियों की गुणवत्ता और समानता के लिए महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। कई देशों की स्कूल कैलेंडर संरचना ऋतुओं की तुलना में औपनिवेशिक इतिहास के प्रभाव के कारण अधिक है, और स्थानीय कृषि चक्रों के अनुरूप नहीं है। स्कूल शुरू होने का समय भी मायने रखता है। अधिक सोने के समय की अनुमति देने के अलावा, देर से शुरुआत किशोरों की सर्केडियन लय अर्थात् सुबह और शाम के समय अत्यधिक सतर्कता बरतने के साथ बेहतर ढंग से सामंजस्य स्थापित करती प्रतीत होती है।

लक्ष्य 4.ख. छात्रवृत्ति

2015 और 2019 के बीच छात्रों द्वारा उत्तीर्ण होने पर स्कूल बदलने में सहायता करने के लिए कुल सहायता 30% बढ़कर 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। कम आय वाले देशों को कुल छात्रवृत्ति सहायता 2015 से 2019 तक दोगुनी हो गई है, जो उच्च स्तरीय दाखिले में वृद्धि से अधिक है। लेकिन निम्न और

मध्यम आय वाले दोनों देशों को ध्यान में रखते हुए, अन्यत्र जाने वाले छात्रों की संख्या छात्रवृत्ति सहायता में वृद्धि से कहीं अधिक है। औसतन, प्रति अंतर्राष्ट्रीय छात्र, 2006 की तुलना में 2019 में कम छात्रवृत्ति सहायता उपलब्ध थी। उपलब्ध असमान आंकड़े बताते हैं कि 2020 तक छात्रवृत्ति में पर्याप्त विस्तार का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। लेकिन दाताओं द्वारा अब 2015 की तुलना में अधिक विकासशील देशों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की संभावना है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राप्तकर्ता देशों के एक या दो प्रमुख दाताओं पर निर्भर होने की संभावना कम है।

'प्रतिभा पलायन' की अवधारणा, जहां छात्रवृत्ति पर जाने वाले छात्र अपने मूल देशों में नहीं लौटते हैं, को 'प्रतिभा परिसंचरण' की अधिक परिष्कृत समझ द्वारा बदला जा रहा है। हाल के अनुमान बताते हैं कि उप-सहारा अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में वापस आने वाले प्रवासी काफी बड़े हिस्से को दर्शाते हैं, और यह कि ये प्रवासी औसतन अधिक शिक्षित हैं। कुछ देश यह मानते हैं कि अत्यधिक कुशल नागरिक भी जो निकट भविष्य में वापस नहीं लौटेंगे यदि उचित प्रकार से संपर्क में हैं तो एक संपत्ति ही हैं। प्रवासी नीति सूचकांक के लिए विश्लेषण किए गए 22 लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देशों में से 8 औपचारिक प्रतिभा परिसंचरण नेटवर्क बनाए रखा। सभी विश्व क्षेत्रों, आय स्तरों और सरकारी टाइप को शामिल करने वाले 35 देशों की प्रवासी नीतियों के पूर्व प्रारूप में पाया गया कि दो-तिहाई ने अपने देश में किसी न किसी तरह के वैज्ञानिक नेटवर्क को बनाए रखा और छात्रवृत्ति पर विदेश भेजे गए आधे छात्रों पर वापस आने की बाध्यता शर्त लगाई थी।

लक्ष्य 4.ग. शिक्षक

रिपोर्ट किए गए डेटा दर्शाते हैं कि उप-सहारा अफ्रीका वह क्षेत्र है जहां राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाले शिक्षकों का प्रतिशत सबसे कम है: पूर्व-प्राथमिक में 57% (बनाम लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में 83%), प्राथमिक में 67% (बनाम उत्तरी अफ्रीका में 85%) और पश्चिमी एशिया) और माध्यमिक शिक्षा में 61% (बनाम मध्य और दक्षिणी एशिया में 78%)। इसलिए, 2015 के बाद से थोड़ा सुधार होने के बावजूद, उप-सहारा अफ्रीका में छात्र/ प्रशिक्षित शिक्षक अनुपात वैश्विक औसत से लगभग दोगुना है।

यहां तक कि योग्य शिक्षक भी उस विशिष्ट विषय के लिए योग्य नहीं हो सकते हैं जो वे पढ़ाते हैं। अपने विषय से अलग विषय पढ़ाना दुनिया के अधिकांश हिस्सों में प्रचलित है। 2018 टीचिंग एंड लर्निंग इंटरनेशनल सर्वे में भाग लेने वाली कम से कम 40 शिक्षा प्रणालियों में, निचले माध्यमिक विद्यालय के 10% से अधिक विज्ञान शिक्षकों ने इस विषय में कोई औपचारिक शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था। यही हाल गणित के शिक्षकों का है। जॉर्जिया और सऊदी अरब में, विज्ञान और गणित के 60% से भी कम शिक्षकों ने औपचारिक शिक्षा के भाग के रूप में अपने विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अपने विषय से अलग विषय पढ़ाना समानता संबंधी समस्याएं पैदा करता है, क्योंकि सभी के समान रूप से अपने विषय से अलग विषय पढ़ाने वाला शिक्षक होने की संभावना नहीं है, जो प्राय: ग्रामीण इलाकों और मूलभूत संसाधनों के अभाव वाले छात्रों की सेवा करने वाले स्कूलों में अधिक आम है।

शिक्षक वेतन संकेतक पर नया यूआईएस अनुमान, जो इस बात की जांच करता है कि योग्यता के समकक्ष स्तर की आवश्यकता वाले अन्य व्यवसायों के सापेक्ष शिक्षक का स्तर कहां हैं, यह दर्शाता है कि एक ही देश के भीतर विभिन्न शिक्षा स्तरों पर शिक्षकों के बीच औसत अंतर आम तौर पर देशों के बीच मतभेदों की तुलना में छोटा होता है। उच्च आय वाले देशों में, जहां से अधिकांश साक्ष्य मिलते हैं, शिक्षकों को अन्य क्षेत्रों में समकक्ष पेशेवरों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है (**चित्र 8**)।

शिक्षक वेतन संकेतक शिक्षक प्रेरणा के लिए एक प्रॉक्सी माना जाता है। लेकिन कई और कारक प्रेरणा को प्रभावित करते हैं, जैसा कि आठ पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीकी देशों में शिक्षक अनुपस्थिति के हाल के विश्लेषण से पता चलता है। यहां तक कि शिक्षक की अपनी रिपोर्ट के अनुसार, सप्ताह में कम से कम एक बार स्कूल से अनुपस्थित लोगों की हिस्सेदारी केन्या और रवांडा में 10% से कम से लेकर दक्षिण सूडान में लगभग 30% तक है। शिक्षकों का कहना है कि वे स्वास्थ्य (62%) और पारिवारिक आधार (35%), इसके बाद मौसम (विशेषकर भारी बारिश और अत्यधिक गर्मी), आधिकारिक व्यवसाय और परिवहन की समस्याओं के कारण अनुपस्थित हैं।

शिक्षा में अन्य एसडीजी

बच्चों को शिक्षा गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देने में घर पर बिजली की पहुंच महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भूटान के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम ने ईंधन की लकड़ी के उपयोग को कम करने में मदद की और स्कूली शिक्षा 0.8 साल तक बढ़ गई, जिसका लड़कों की तुलना में लड़कियों पर अधिक प्रभाव पड़ा। स्कूलों में बिजली तक पहुंच सीखने के माहौल को बेहतर बनाने और सीखने के संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने में मदद कर सकती है। ऊर्जा क्षेत्र प्रबंधन सहायता कार्यक्रम ने पाया कि केन्या में 72% स्कूल, लेकिन इथियोपिया में केवल 22%, की राष्ट्रीय सार्वजनिक ग्रिड तक पहुंच थी। सड़कें गरीबी को कम करने और शिक्षा के परिणामों सहित आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। एंटिओक्विया के कोलंबियाई विभाग में, बेहतर ग्रामीण सड़कों को ग्रामीण छात्रों के लिए बेहतर शिक्षा प्रदर्शन से जोड़ा गया था।

2030 तक एसडीजी हासिल करने की दौड़ में, अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी में सुधार के लिए उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जो सौर और पवन ऊर्जा के

परिवर्तन में बड़े निवेश द्वारा समर्थित है। सतत उपभोग और उत्पादन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता भी बढ़ रही है। हालांकि, ऐसे लक्ष्यों के क्षेत्रों में सुधार जो बाजार उन्मुख नहीं हैं - जैसे स्वच्छ खाना पकाने की तकनीक तक समान पहुंच, नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेषज्ञता, क्षमता निर्माण के लिए कम से कम विकसित देशों को वित्तीय सहायता, विविध और समान कार्यबल विकास – को संघर्ष द्वारा दर्शाया गया है। शिक्षा स्थिरता उद्देश्यों की उपलब्धि का समर्थन करती है। शिक्षा संस्थानों को ऊर्जा और अन्य स्थिरता चुनौतियों के बारे में छात्रों की समझ में सुधार करने की जरूरत है। जन जागरूकता व्यापक सामाजिक परिवर्तन में योगदान कर सकती है। हरित परिवर्तन का समर्थन करने के लिए व्यावसायिक क्षमता विकास को तेज गति से करने की आवश्यकता है।

वित्त-पोषण की निगरानी

कुल सार्वजनिक व्यय में शिक्षा का हिस्सा 2000 में 13.8% से बढ़कर 2019 में 14.1% हो गया। 71 देशों के हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि 2021 में यह हिस्सा घटकर 13.5% हो गया, जो कोविड-19 के अत्यधिक प्रभाव को दर्शाता है। 2014-19 के डेटा वाले 151 देशों में से, 48 देश, या 32%, जीडीपी के 4% और शिक्षा पर सरकारी खर्च के 15% के दोनों बेंचमार्क से चूक गए। कुछ देश ऐसे कार्यक्रमों को शुरू करने में काफी प्रभावी हैं जो सबसे अधिक वंचितों तक पहुंचते हैं। अल्जीरिया 3 मिलियन प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को 23 अमेरिकी डॉलर के बराबर वार्षिक शिक्षा भत्ता प्रदान करता है: 38% सबसे गरीब लेकिन 10% सबसे अमीर सहायता प्राप्त करते हैं।

2019 में शिक्षा के लिए सहायता 15.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर स्थिर रही। सहायता प्रभावशीलता का अर्थ अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग हैं। एक परिभाषा देश के स्वामित्व और परिणामों, पारदर्शिता और पारस्परिक जवाबदेही और समावेशी विकास भागीदारी पर केंद्रित है। कुल सहायता में प्रत्यक्ष बजट समर्थन का हिस्सा 2002 में 6.6% से गिरकर 2019 में 2.5% हो गया।

2010 के दशक में लगभग 100 निम्न और मध्यम आय वाले देशों की घरेलू बजट सर्वेक्षण रिपोर्टों के विश्लेषण में पाया गया कि शिक्षा कुल घरेलू खर्च का 3.2% है, जो रवांडा, युगांडा और जाम्बिया सहित हैती और लेबनान और उप-सहारा अफ्रीकी देशों में 6% या उससे अधिक तक पहुंच गया है।

चित्र 8:

अन्य पेशेवरों की तुलना में, शिक्षक उच्च आय में अपेक्षाकृत कम वेतन अर्जित करते हैं लेकिन कुछ निम्न और मध्यम आय वाले देशों में उच्च वेतन प्राप्त करते हैं।

अन्य व्यवसायों के सापेक्ष औसत शिक्षक वेतन की योग्यता के अनुसार तुलना करने की आवश्यकता है, नवीनतम वर्ष 2015-19 में उपलब्ध है



जीईएम सांख्यिकी लिंक: https://bit.ly/GEM2021_Summary_fig8

स्रोत: यूआईएस डेटाबेस।

शिक्षा में गैर-सरकारी कार्यकर्ता:

कौन चुनता है? कौन वंचित रह जाता है?

गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं की भूमिका स्कूली शिक्षा के प्रावधान से लेकर विभिन्न शिक्षा स्तरों और प्रभाव क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने तक व्याप्त है। कोविड-19 महामारी के प्रभाव से प्राप्त साक्ष्यों सहित एसडीजी 4 की प्रगति की समीक्षा के साथ, 2021/2 वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट सरकारों से सभी संस्थानों, छात्रों और शिक्षकों को एक ही प्रणाली के भाग के रूप में देखने का आग्रह करती है। मानकों, सूचनाओं, प्रोत्साहनों और जवाबदेही से सरकारों को विशेषाधिकार या शोषण को नज़रअंदाज किए बिना सभी के शिक्षा के अधिकार की रक्षा, सम्मान और पूरा करने में मदद करनी चाहिए। सरकारी रूप से वित्त-पोषित शिक्षा को सार्वजनिक रूप से प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शिक्षा प्रक्रियाओं, छात्र परिणामों और शिक्षक की कार्य स्थितियों में असमानता का समाधान किया जाना चाहिए। दक्षता और नवाचार कोई व्यावसायिक रहस्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका विस्तार किया जाना चाहिए और सभी के द्वारा अपनाया जाना चाहिए। इसके लिए निहित स्वार्थों को दरकिनार करने के लिए सार्वजनिक शिक्षा नीति प्रक्रिया में पारदर्शिता और अखंडता बनाए रखने की आवश्यकता है।

रिपोर्ट में की गई अपील - कौन चुनता है? कौन वंचित रह जाता है? - नीति निर्माताओं को मौलिक विकल्पों के संदर्भ में गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं से संबंधों जैसे: समानता और पसंद की स्वतंत्रता के बीच; पहल को प्रोत्साहित करने और मानकों को स्थापित करने के बीच; विभिन्न साधनों और जरूरतों के समूहों के बीच; एसडीजी 4 के तहत तत्काल प्रतिबद्धताओं और प्रगतिशील रूप से महसूस की जाने वाली प्रतिबद्धताओं के बीच (उदाहरण के लिए माध्यमिक शिक्षा के बाद); और शिक्षा और अन्य सामाजिक क्षेत्रों के बारे में प्रश्न पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है।

पांचवीं वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट का समर्थन करने के लिए दो ऑनलाइन टूल हैं: पीयर, एक नीतिगत संवाद संसाधन जो गैर-सरकारी गतिविधि और दुनिया की शिक्षा प्रणाली के विनियमों का उल्लेख करता है; और एक नई वेबसाइट देखें, जो स्रोतों को समेकित करती है और समय के साथ नई पूर्णता दर अनुमान प्रदान करती है।

unesco
Global Education Monitoring Report

4 QUALITY EDUCATION

Sustainable Development Goals

www.unesco.org/publishing • wwww.unesco.org/gemreport